महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

सुविचार

संतोष और गहरी नींद, मिल जाने के बाद ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता, सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीजों के बीच है...

वर्ष : 17 अंक : 02 | उज्जैन, शुक्रवार 12 जून 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

न्यूज ब्रीफ

ई22, ई25, ई27 और ई30 पर एक्साइज ड्यूटी माफ, कितना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल?

नई दिल्ली/ जीएनएस। सरकार ने ई22 से ई30 यानी 22, 25, 27 व 30 फीसद इथेनोल मिश्रित पेट्रोल पर पूर्ण उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। इन वेरिएंट्स पर शून्य शुल्क की दर लागू होगी। सरकार का दावा है कि यह कदम इथेनोल मिश्रण को बढ़ावा देने, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उत्पाद शुल्क पूरी तरह से घटाने का मतलब यह हुआ कि उक्त चारों तरह के मिश्रित ईंधन की कीमत मौजूदा पेट्रोल (ई20) से कम होगी। वैसे बाजार में अभी तेल कंपनियां उक्त मिश्रण वाले ईंधन नहीं बेचती हैं, लिहाजा भविष्य में जब इनकी बिक्री सुनिश्चित की जाएगी तो संभवतः ई20 के मुकाबले 20 फीसद से ज्यादा एथोनोल मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। इस बारे में सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से अभी स्पष्टीकरण आना शेष है। तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एक तरह से ज्यादा मिश्रित इथेनोल के लिए देश में इकोसिस्टम को बनाने के लिए है। सरकार की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि वह कब से ई20 से ज्यादा मिश्रण के पेट्रोल की बिक्री देश में शुरू करेगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले दिनों ई85 ईंधन से चलने वाली कार की लांचिंग के अवसर पर कहा था कि यह ई20 से करीब 20 फीसद सस्ता होगा और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ई85 इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि ई20 ईंधन की पूरी समीक्षा के बाद ही सरकार आगे के रोडमैप पर आगे बढ़ेगी। बहरहाल, यह साफ है कि चूंकि बाजार में अभी ई20 से ज्यादा के मिश्रण वाला पेट्रोल की उपलब्धता नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ नहीं मिलेगा।

बिहार में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर मिलेगा बंपर फायदा, नए वाहन पर 50% टैक्स छूट

पटना/ जीएनएस। बिहार में पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप गैर-सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद वाहन मालिकों के लिए पुरानी गाड़ियों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा कराना आसान होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। नए नियमों के तहत वाहन स्क्रैप कराने वाले मालिकों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण होगा कि वाहन को अधिकृत केंद्र पर स्क्रैप किया गया है। इस सीओडी के आधार पर वाहन मालिक नया वाहन खरीदते समय मोटर वाहन कर में विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे। संशोधित व्यवस्था के तहत स्क्रैप किए गए वाहन के बदले नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोग पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर नए एवं सुरक्षित वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत तक मोटरयान कर में छूट का प्रावधान है। वहीं भारत स्टेज-1 और भारत स्टेज-2 मानकों के तहत निर्मित कुछ मध्यम एवं भारी मालवाहक तथा यात्री वाहनों पर 50 प्रतिशत तक कर छूट दी जाती है।

मध्यप्रदेश समावेशी विकास, नवाचार और जनकल्याण के दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर बढ़ रहा आगे : मुख्यमंत्री

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बताई गई मध्यप्रदेश की उपलब्धियां

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्नों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि काउंसिल की बैठक में विकसित भारत ञ2047 के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी, समन्वित प्रयासों तथा विकास के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भी विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुशासन, समावेशी विकास, नवाचार और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है।

नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब देंगे विकास को गति- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश को नक्सलवाद का खात्मा केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा से पहले करने में सफलता मिली है। प्रदेश के जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां विकास की गति तेज की जाएगी। युवाओं के विकास पर विशेष रूप से जोर रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में बहनों और बेटियों की उन्नति, कृषक कल्याण, नए मेडीकल कॉलेजों के माध्यम से उपचार कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए बेहतर कार्य हो रहा है। इसी तरह आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश अग्रसर है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी की गई है। पीएमश्री महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को अनेक संकायों और विषयों के अध्ययन से जोड़ा गया है। कौशल विकास और औद्योगिकीकरण के प्रयास तेज हुए हैं। देश में सबसे पहले पीएम मित्र पार्क की धार जिले में स्थापना हुई है, यहां शीघ्र ही इकाइयों द्वारा रिकार्ड समय में कार्य प्रारंभ हो रहा है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के वेस्ट को निष्पादित करने के साथ ही प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से अनेक नए कार्य प्रारंभ करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में मुख्यतः मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण एवं सभी के लिए समानता और गरिमा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

नन्हें हाथों में सपनों की रोशनी देने का संकल्प- प्रहलाद सिंह पटेल

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल होता है, जब आँखों में अनगिनत सपने पलते हैं, मन कल्पनाओं के आकाश में उड़ान भरता है और भविष्य की संभावनाएं आकार लेती हैं। यह वह समय है, जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, पैरों में खेल की चंचलता और चेहरे पर निश्छल मुस्कान। समाज का एक कटु सत्य यह भी है कि आज भी अनेक बच्चों का बचपन अभाव, नशा, गरीबी और श्रम के बोझ तले दबा हुआ है। उनके नन्हें हाथ, जो कलम थामने के लिए बने थे, आज मजदूरी के कठिन कार्यों में उलझे दिखाई देते हैं। अनाथों की तरह उनका यह जीवन हमारे समाज की संवेदनहीनता और सामूहिक विफलता का परिणाम है।

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा समाज बना पाए हैं, जहां उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सहज रूप से प्राप्त हो सके? यदि नहीं, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि मानवता के मूल्यों के विरुद्ध अपराध है। किसी भी बच्चे को उसकी उम्र से पहले जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए विवश करना उसके अधिकारों का हनन है।

बच्चों का स्थान कारखानों, दुकानों, ढाबों और खतरनाक कार्यस्थलों पर नहीं, बल्कि विद्यालयों, खेल के मैदानों और परिवार के स्नेहिल वातावरण में होना चाहिए। हमारा श्रमोदय विद्यालय इस भावना का मूल स्वरूप हैं। कोई बच्चा जब मजदूरी करता है, तब केवल उसका वर्तमान ही नहीं, बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता है। उसके सपने सीमित हो जाते हैं और उसके विकास की संभावनाएं बाधित हो जाती हैं।

मध्यप्रदेश सरकार बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है-÷बंधुआ और बाल श्रम मुक्त मध्यप्रदेश÷। यह केवल एक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान है। हम ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां किसी भी बच्चे को मजबूरी में श्रम न करना पड़े और प्रत्येक बच्चे को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

हाफ-पैंट में पुष्पा की परेडः जहांगीर खान को पुलिस ने सड़कों पर घुमाया, वीडियो वायरल

कोलकाता/ जीएनएस। जबरन वसूली और अन्य मामलों में गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को उनके विधानसभा क्षेत्र फलता में हाफ-पैंट में घुमाया गया।

पुलिस ने फलता विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर जहांगीर खान की परेड निकाली। पुलिसकर्मी चारों तरफ से जहांगीर को घेरकर चल रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हाफ-पैंट में पुष्पा की परेड- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता का चुनाव काफी चर्चा में रहा। इस क्षेत्र में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के धाकड़ अधिकारी अजयपाल शर्मा को चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया था। अजयपाल शर्मा को क्ककका सिंघम कहा जाता है।

अजयपाल शर्मा ने जहांगीर खान के घर पहुंचकर उसे चेतावनी दी थी कि अगर जनता को डराकर वोट डलवाने की कोशिश न करे। इसके बाद जहांगीर खान ने कहा था, कि अगर वो सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं।

इस बार के फलता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जहांगीर खान को हार का सामना करना पड़ा। अब जबरन वसूली और अन्य मामलों में जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

एंथ्रोपिक्स के AI मॉडल माइथोस से निपटेगी इंफोसिस, बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए सरकार ने कसी कमर

नई दिल्ली/ जीएनएस। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी एंथ्रोपिक्स के एआई मॉडल माइथोस से होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने काम करना शुरू कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में ही माइथोस से बैंकिंग सेक्टर के डाटा और साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की आशंका को देखते हुए बैंकों को इसके बचाव की तैयारी करने का निर्देश दिया था।

वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के बाद से ही माइथोस से बचने के लिए काम चल रहा है। एक समिति भी इसकी निगरानी कर रही है।

भारतीय बैंकों को साइबर हमलों का खतरा- सूत्रों का कहना है कि निजी सेक्टर की आईटी कंपनी इंफोसिस इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर बैंककर्मी को प्रशिक्षित करेगा ताकि बैंकों को साइबर हमले से बचाया जा सके।

इलेक्ट्रानिक्स व आईटी मंत्रालय की भी इस काम में मदद ली जा रही है। माइथोस एक ऐसा एआई मॉडल है तो जो डाटा सुरक्षा व साइबर सुरक्षा से जुड़े किसी भी साफ्टवेयर को हैक कर सकता है।

गत बुधवार को एंथ्रोपिक्स ने माइथोस एआई मॉडल को लांच तो कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल माइथोस का इस्तेमाल साइबर सुरक्षा और केमिकल फार्मूला जैसी चीजों में सेंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा की चोरी पर सियासत तेज, महंत कमल नयन दास के साथ बृजभूषण शरण और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाया सवाल

लखनऊ/ जीएनएस। राम नगरी अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर के मंदिरों से दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चढ़ावा की धनराशि लगातार चोरी होने से संतों के साथ ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं।

महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के साथ ही कैसरगंज के भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी राम मंदिर के दानपात्र से चढ़ावा गायब होने को भक्तों की आस्था पर कुठाराघात बता रहे है। रामजन्मभूमि परिसर के दानपात्रों से बड़ी रकम के गबन के आरोप के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतनी बड़ी धनराशि के गबन के बावजूद ट्रस्ट ने अब तक इस मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं कराई है। इस विषय पर जब जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य अनलि मिश्र ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया।

दूसरी ओर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव ने तो सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। गबन प्रकरण में एक के बाद एक जानकारी सामने आने के बाद यह आशंका जताई जाने लगी है कि इसमें गणना कक्ष के आसपास लगे सुरक्षा कर्मी आखिर क्या जांच करते रहेष यदि गणना में संलग्न कर्मियों की जांच ठीक से हुई होती, तो कैसे इतनी बड़ी रकम परिसर से बाहर निकल पाती। गणना कक्ष के आसपास निजी एजेंसियों के साथ पुलिस व सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

बरेली-शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक की होगी मरम्मत, 15 जून तक देरी से चलेंगी ये 6 ट्रेनें

बरेली/ जीएनएस। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के बरेली-शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जाएगी। बंथरा, तिलहर एवं मीरानपुर कटरा स्टेशनों पर ट्रैक टैंपिंग कार्य की वजह से 12 से 15 जून तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसकी वजह से छह ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों से चार-चार घंटे की देरी से चलाई जाएंगी। इसके अलावा कई ट्रेनें काशन देकर गुजारी जाएंगी। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी होगी।

रेलवे के मुताबिक 15074 टनकपुर-सिंगरौली एक्सप्रेस 12 से 15 जून तक टनकपुर से, 15076 टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस 13 जून को टनकपुर से, 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 12 और 14 जून को जम्मूतवी से, 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 12 और 14 जून को लालगढ़ से आदी।

ममता बनर्जी को चौथा झटकाः चार दिन में 4 इस्तीफे, कोयल मल्लिक ने भी छोड़ा दीदी का साथ; क्या है राज्यसभा का नंबर गेम?

कोलकाता/ जीएनएस। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है।

गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक और अभिनेत्री-सांसद कोयल मल्लिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पिछले चार दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तृणमूल सांसदों की संख्या चार हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव भी उच्च सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं।

प्रकाश चिक बड़ाईक ने इस्तीफे के बाद कहा कि हालिया चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने तृणमूल छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में वह मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही काम करेंगे।

कभी अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले बड़ाईक को 2023 में तृणमूल ने राज्यसभा भेजा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीपुरद्वार से उम्मीदवार भी बनाया था। उन्होंने पार्टी के भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

उधर, कोयल मल्लिक के इस्तीफे ने तृणमूल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। फरवरी में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था और अप्रैल में उन्होंने सांसद पद की शपथ ली थी। उस समय उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बताया था, लेकिन अब पार्टी से दूरी बना ली है।

लगातार इस्तीफों के कारण राज्यसभा में तृणमूल की संख्या 13 से घटकर नौ रह गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा में भी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है, जहां बड़ी संख्या में सांसदों के असंतुष्ट खेमे के साथ जाने की चर्चा है।

हालांकि इस उथल-पुथल के बीच अभिनेता-सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में वह न तो पार्टी छोड़ेंगे और न ही अपनी नेता का साथ। उनके अनुसार राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नैतिक रूप से इस समय ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहना ही उचित है।

पंजाब में बीजेपी और अकाली दल मिलकर लड़ेंगें 2027 का चुनाव? गठबंधन को लेकर हलचल हुई तेज

चंडीगढ़/ जीएनएस। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ी पार्टी के साथ किसी भी तरह के समझौते से भाजपा के इनकार के बाद बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया बयान को अकाली दल के साथ रिश्तों की नई संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है।

भाजपा के प्रदेश महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन राजू ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह की पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में 2027 का चुनाव सभी 117 सीटों पर अपने दम पर लड़ेगी। राजू के इस बयान ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है कि भाजपा किन राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है। इसी बीच, दिल्ली में एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य पंजाब में संगठन को मजबूत करना है और वह सभी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी सभी विकल्पों पर नजर रखे हुए है।

राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान को शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित संवाद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा और अकाली दल के रिश्तों का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है।

तीन दशक से अधिक समय तक दोनों दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी रहे, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद 2022 और 2024 के चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़े।

लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पुनर्विकास में बड़ी उपलब्धि: नए भवन से जल्द शुरू होगा ट्रेन संचालन, यात्रियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतर्गत इंदौर स्थित लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। स्टेशन के नए भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और पुराने स्टेशन भवन से परिचालन एवं तकनीकी व्यवस्थाओं को नए भवन में स्थानांतरित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में 11 जून को स्टेशन पर मेजर ब्लॉक लेकर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य संपन्न किया गया, जिससे नए भवन से ट्रेन संचालन व्यवस्था शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

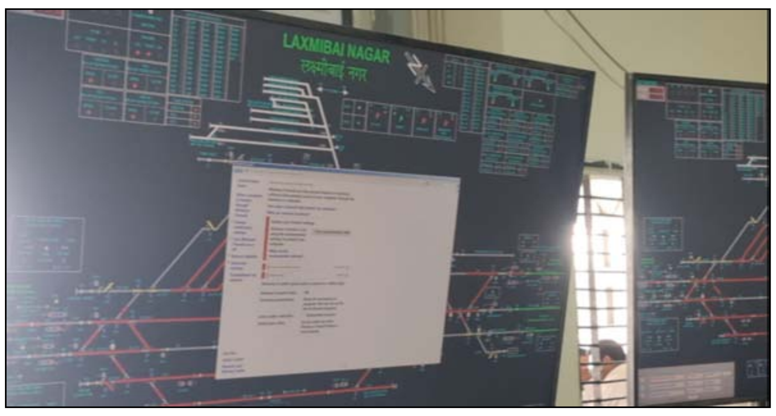

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को सुरक्षित एवं निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए व्यापक तकनीकी तैयारियां की गईं। कार्य के दौरान चार लोकल ट्रेनों को निरस्त किया गया, जबकि आठ ट्रेनों को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से शॉर्ट टर्मिनेट एवं शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया। इसके अलावा दस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया गया ताकि कार्य बिना किसी बाधा के शीघ्र पूरा हो सके।

इस दौरान स्टेशन एवं यार्ड क्षेत्र में सिग्नलिंग प्रणाली, ट्रैक सर्किट और अन्य सुरक्षा उपकरणों में आवश्यक बदलाव किए गए। स्टेशन की परिचालन व्यवस्था पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित होने के कारण सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग प्रणाली को नए उपकरणों के अनुरूप पुनर्संयोजित किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार के कार्यों के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है।

कार्य की निगरानी के लिए पश्चिम रेलवे के मुख्य इंजीनियर (निर्माण) धीरज कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) कुंजीलाल मीना सहित संकेत एवं दूरसंचार, परिचालन, इंजीनियरिंग तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी स्टेशन पर मौजूद रहे। सभी विभागों द्वारा समन्वय के साथ कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार 12 जून की रात्रि से नए स्टेशन भवन में स्थापित ट्रेन परिचालन प्रणाली को चालू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से स्टेशन यार्ड में प्वाइंट एवं क्रॉसिंग बिछाने, ट्रैक लिंकिंग, केबलिंग तथा आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था स्थापित करने का कार्य लगातार जारी है।

नए भवन में स्टेशन मास्टर कक्ष, रिले रूम, आईपीएस रूम सहित अन्य परिचालन इकाइयों का निर्माण और उपकरणों की स्थापना लगभग पूर्ण हो चुकी है। साथ ही यात्री सुविधाओं, टिकट बुकिंग व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को भी नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी यात्री सेवाएं नए स्टेशन भवन से संचालित होने लगें।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि पुराने स्टेशन भवन से परिचालन एवं प्रशासनिक गतिविधियां पूरी तरह स्थानांतरित होने के बाद पुराने भवन को हटाकर प्लेटफॉर्म क्रमांक एक और दो के निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। योजना के अनुसार अगले एक से डेढ़ माह में दोनों प्लेटफॉर्मों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक रेलवे अवसंरचना उपलब्ध हो सकेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए नए स्टेशन भवन से वर्तमान प्लेटफॉर्म तक पहुंचने हेतु अस्थायी मार्ग भी तैयार किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री टिकट लेकर आसानी से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। यह सुविधा स्टेशन परिसर के विकास कार्य पूर्ण होने तक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का नया भवन आधुनिक वास्तुकला, उन्नत तकनीकी संसाधनों और बेहतर यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पुनर्विकास कार्य पूर्ण होने के बाद यह स्टेशन इंदौर क्षेत्र के प्रमुख आधुनिक रेलवे स्टेशनों में शामिल होगा और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं का अनुभव प्रदान करेगा।

मुख्य रेलवे स्टेशन बारिश में पूरी तरह हो जाएगा जमींदोज, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन सिंहस्थ-2028 को देखते हुए रेलवे द्वारा रतलाम मंडल अंतर्गत इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन नया एवं भव्य आकार लेगा, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। वर्षाकाल के दौरान ही वर्तमान रेलवे स्टेशन भवन को जमींदोज करने का काम होगा। जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ेगी। प्लेटफार्म एक पर स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही पार्सल कार्यालय के पास वाले हिस्से में काम चल रहा है। इससे यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। स्टेशन से कुल 23 कार्यालय स्थानांतरित होंगे। यात्रियों को ये पता करने में भी परेशानी का सामना करना होगा कि कौन-सा कार्यालय कहां पर स्थानांतरित हुआ है। पटेल ब्रिज की तरफ पार्सल कार्यालय के पास पिछले आठ महीने से खोदाई जारी है। अब तक सिर्फ वाटर प्रूफिंग का काम पूरा हुआ है। वहीं, लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को जनवरी 2026 में पूरी क्षमता के साथ शुरू करने का रेलवे अधिकारियों ने दावा किया था, लेकिन यहां भी निर्माण कार्य अधूरा है। इसको पूरा होने में लगभग छह महीने और लगेंगे। उधर, इंदौर-धार, इंदौर-खंडवा, इंदौर-मनमाड़ और इंदौर-बुधनी रेल परियोजनाओं के काम भी धीमी गति से चल रहे हैं।

यात्रियों के लिए आवागमन होगा बंद- मोंटे कार्लो लिमिटेड कंपनी को 412 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य रेलवे स्टेशन पर जी-प्लस सेवन भवन का निर्माण कार्य 42 महीने में पूरा करना है। इसमें मल्टीलेवल पार्किंग, यात्री प्रतीक्षालय कक्ष, हाईटेक प्लेटफार्म और अन्य सुविधाएं रहेंगी। पार्सल कार्यालय के पास वाटर प्रूफिंग का काम पूरा हो गया है। यह काम सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए समय लगा।

वर्षाकाल से पहले निगम की कार्रवाई तेज, दो जर्जर भवन हटाए गए

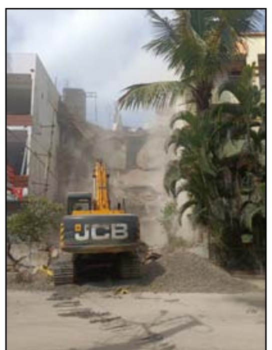

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वर्षाकाल के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के जर्जर एवं खतरनाक भवनों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार गुरुवार को झोन क्रमांक-3 क्षेत्र में दो अत्यंत जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम भवन शाखा द्वारा किए गए निरीक्षण में स्नेहलतागंज क्षेत्र स्थित सतीश निगम के स्वामित्व वाला जी+3 भवन अत्यधिक जर्जर पाया गया। भवन की स्थिति जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही थी। इसी प्रकार काछी मोहल्ला क्षेत्र में स्थित दिनेश कुशवाहा के मकान को भी अत्यंत जर्जर और दुर्घटना की दृष्टि से जोखिमपूर्ण पाया गया। भवन अधिकारी पल्लवी पाल ने बताया कि दोनों भवनों के संबंध में नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर निगम के अमले द्वारा दोनों भवनों को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी पल्लवी पाल, भवन निरीक्षक, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे सहित नगर निगम का संबंधित अमला मौजूद रहा। निगम अधिकारियों ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए शहरभर में जर्जर भवनों का सर्वे लगातार किया जा रहा है और जहां भी जनसुरक्षा के लिए खतरा पाए जाने वाले भवन चिन्हित होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता, 2026 में पीड़ितों को लौटाए 2.84 करोड़ रुपये

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इंदौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों ने वर्ष 2026 में अब तक उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड से पीड़ित नागरिकों को 2 करोड़ 84 लाख 8 हजार 831 रुपये की राशि वापस दिलाई है।

क्राइम ब्रांच को वर्ष 2026 में मई माह तक प्राप्त लगभग 4,575 साइबर फ्रॉड शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह राशि आवेदकों को सुरक्षित वापस कराई गई। केवल मई 2026 में ही 47 लाख 31 हजार 255 रुपये की राशि पीड़ितों को लौटाई गई है।

साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत क्राइम ब्रांच ने हजारों फर्जी बैंक खातों को फ्रीज कराया है। इसके अलावा 200 से अधिक हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम खाते शामिल हैं, को रिकवर कराया गया। वहीं आवेदकों के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर बनाए गए 280 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कराए गए हैं।

पुलिस के अनुसार सबसे अधिक शिकायतें संदिग्ध एपीके फाइलों के माध्यम से की गई धोखाधड़ी, ऑनलाइन निवेश संबंधी फ्रॉड, बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट या रिवॉर्ड प्वाइंट रिडीम कराने के नाम पर ठगी तथा ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से संबंधित प्राप्त हुई हैं।

क्राइम ब्रांच इंदौर न केवल साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बल्कि जन-जागरूकता अभियान भी लगातार चला रही है। विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों लोगों को साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है।

इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए 'सेफ क्लिक्स-एआई एजेंटिक सॉल्यूशंस' चैटबॉट का उपयोग करें और किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930, क्राइम ब्रांच इंदौर की साइबर हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में होगा सामूहिक योग कार्यक्रम

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कुलसचिवों, प्राचार्यों एवं संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित गतिविधियों का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से कहा गया है कि वे योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम की तैयारी के तहत 19 जून 2026 को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को योग के अनुरूप आरामदायक वेशभूषा धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को योग दिवस कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हर घर जल संरक्षण बने जनआंदोलन: महापौर पुष्यमित्र भार्गव

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संचयन से जोड़ने के उद्देश्य से महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा-1 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-9 का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया तथा नागरिकों को वर्षा जल संचयन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

दौरे के दौरान महापौर ने क्षेत्र में स्थापित वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन किया और उन घरों का भी निरीक्षण किया, जहां रहवासी वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे परिवारों की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण की यह पहल समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

स्थानीय नागरिकों से संवाद करते हुए महापौर ने कहा कि जल संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी भी है। यदि हर घर में वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था विकसित हो जाए तो भविष्य में जल संकट की चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से जल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने मानसून पूर्व तैयारियों की भी समीक्षा की और नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, वहां समय रहते सुधारात्मक कार्य किए जाएं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से संकरी गलियों और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाने तथा नालियों में जमा गाद, कचरा एवं अन्य अवरोधों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।

महापौर ने अधिकारियों से जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने को कहा ताकि वर्षा के दौरान पानी का प्रवाह बाधित न हो और जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने मानसून पूर्व सभी ड्रेनेज एवं सफाई कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही महापौर ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क खुदाई कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां-जहां सड़कें खोदी गई हैं, वहां रेस्टोरेशन का कार्य बारिश शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा सकते हैं। इसलिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें।

महापौर ने कहा कि इंदौर की पहचान केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी शहर को देश के लिए उदाहरण बनाना है। इसके लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण आधार है।

इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी एवं एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ला, वार्ड क्रमांक-9 के पार्षद राहुल जायसवाल, महापौर प्रतिनिधि शैलू दवे, नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

निर्माणाधीन मास्टर प्लान सड़कों का आयुक्त ने किया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गुरुवार को शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिंसी चौराहा से रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक तथा मधुमिलन चौराहा से छावनी चौराहा तक निर्माणाधीन मास्टर प्लान सड़कों के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही चंद्रभागा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री नरेश जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयुक्त ने रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से नेमिनाथ जैन मंदिर तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करते हुए पाया कि क्षेत्र में मलबा हटाने का कार्य अपेक्षित गति से नहीं किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वयं बाधक हिस्से हटाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने संबंधित एजेंसी को फटकार लगाई और तत्काल मलबा हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

चंद्रभागा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की धीमी गति पर भी आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

आयुक्त ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देशित किया कि निर्माण क्षेत्रों में पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि आम नागरिकों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए।

जिले में आयोजित होंगे लोक कल्याण मेले

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिले में 12 से 16 जून तक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे। इस तारतम्य में अनुभाग महू में 12, 15 और 16 जून को लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया गया है। यह मेले तहसील कार्यालय महू में होंगे।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश ने देश में एक गौरवशाली और ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। राज्य शासन, नगरीय निकायों तथा ऋणदाता संस्थाओं के समर्पित प्रयासों एवं सक्रिय सहयोग से प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को सफलतापूर्वक लाभान्वित कर उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया जा चुका है। इस योजना की पहुँच को अंतिम छोर तक और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में 01 जून 2026 से विशेष अभियान संचालित किया जा रह है, जो 30 जून तक चलेगा।

जिला स्तर होंगे स्वनिधि महोत्सव- अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालयों पर ÷स्वनिधि महोत्सव÷ का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के सफल लाभार्थियों तथा उनके परिवारजनों की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों, उनके संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियों का उत्सव मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफल वेंडर्स को सम्मानित करना तथा योजना से जुड़े सभी संबंधित हितधारकों के मध्य इसके प्रति और अधिक व्यापक जागरूकता का संचार करना है।

नगरीय निकायों में सजेंगे लोक कल्याण मेले- नगरीय निकाय स्तर पर लोक कल्याण मेलों के माध्यम से पथ विक्रेताओं के लिए सेवाएँ आपके द्वार की पावन संकल्पना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से जरूरतमंद वेंडर्स को वित्तीय, सामाजिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिये बिना गारंटी के 15 हजार रूपये तक की आसान ऋण सुविधा, न्यूनतम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता, क्रेडिट कार्ड एवं डिजिटल लेनदेन के लिए प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकर्स एवं पथ विक्रेताओं की विशेष बैठकें आयोजित कर अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुलभ कराई जाएगी तथा नगरीय निकाय सहायता केंद्रों के माध्यम से वेंडर्स की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

अभियान में सेन्सस टाउन स्तर पर ÷स्वनिधि कैंप÷ का आयोजन कर दूरस्थ व अर्द्धे-शहरी क्षेत्रों में निवासरत पथ विक्रेताओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। विशेष शिविरों के माध्यम से छूटे हुए और नए पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें योजना की जानकारी दी जाएगी। ऋण स्वीकृति के लिए उनके पंजीयन की त्वरित कार्यवाही पूरी की जाएगी जिससे कोई भी पात्र वेंडर लाभ से वंचित न रहे।

मध्य प्रदेश में अगले एक साल में उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन लेगा आकार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें शामिल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर व रतलाम जिले के तहसील और गांवों का क्षेत्रफल भी निर्धारित हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिला पूर्ण रूप से मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल है। वहीं, दूसरे नंबर पर शाजापुर जिले का 90 फीसद हिस्सा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रोपालिटन रीजन में 75 लाख आबादी का आकलन किया गया है, जो संभवतः अब बढ़कर 85 से 90 लाख तक पहुंच चुकी है। आइडीए को कंसल्टेंट मेहता एसोसिएट ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। अब अगले ढाई माह में मेट्रोपालिटन रीजन की सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

इस रिपोर्ट में मेट्रोपालिटन रीजन में शामिल छह जिलों के 50 सेक्टर जिसमें उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयां, हरित क्षेत्र, पुलिस, पीएचई विभागों की मौजूदा योजनाओं का आंकलन किया जाएगा। इसके अलावा इन जिलों में प्रस्तावित भविष्य की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

तीसरे चरण में तैयार होगा रीजनल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्लान- सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होने के बाद अगले छह माह में रीजनल डेवलपमेंट और इंवेस्टमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें विजन के साथ विकास की आगामी क्या रणनीति होगी, उसे शामिल किया जाएगा।

इसमें प्रोजेक्ट का चयन कर चरणबद्ध योजना को तैयार करेंगे। निवेश की योजना के साथ मौजूदा रिसोर्स का उपयोग तय किया जाएगा। इस तरह फाइनल रीजनल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार होगा।

एनसीटीई पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण का आवंटन जारी

विद्यार्थियों को 15 जून तक जमा करना होगा प्रवेश शुल्क

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु संचालित ई-प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एनसीटीई पाठ्यक्रमों (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. आदि) के प्रथम चरण का महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण में पात्र अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये 15 जून 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 64,641 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 59,113 आवेदनों का सत्यापन किया गया।

प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने लॉगिन के माध्यम से आवंटन की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा में शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

मनासा में बिना पंजीयन व अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित दो रेस्टोरेंट शट डाउन

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश तथा एसडीएम सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में *खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच की टीम ने *सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनासा तहसील के दो खाद्य प्रतिष्ठानों को शट डाउन कर खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय बंद कराया है।

देशी तड़का रेस्टोरेंट, बरलाई रोड तलाऊ, तहसील मनासा एवं देशी तड़का रेस्टोरेंट में बासी खाना विक्रय करने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई थी।

टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के गुरुवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर अस्वच्छ परिस्थितियों में सब्जी, रोटी आदि का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय होते पाया गया। किचन में पर्याप्त साफ-सफाई नहीं थी, बर्तन गंदे पाए गए तथा फ्रिज में भी अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का भंडारण मिला। खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्तहो चुका था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान मौके से तैयार लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर एवं आटा सहित कुल 3 नमूनेजांच हेतु लिए गए। जन स्वास्थ्य हित में रेस्टोरेंट का संचालन बंद कराकर परिसर शट डाउन किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल किंगफिशर, रामपुरा रोड फुलपुरा, तहसील मनासा- नियमित निरीक्षण के दौरान होटल किंगफिशर का निरीक्षण किया गया। यहां भी अस्वच्छ परिस्थितियों में मटन, मछली, चिकन, अंडा करी, रोटी, सेव-टमाटर सब्जी आदि का निर्माण एवं विक्रय पाया गया। किचन की दीवारों पर पुताई नहीं थी, गंदगी व्याप्त थी, बर्तन अस्वच्छ थे एवं फ्रिज में खाद्य पदार्थों का भंडारण अस्वच्छ स्थिति में था। वैध खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया।

टीम ने मौके से मक्का आटा सहित कुल 2 नमूने जांच हेतु लिए तथा होटल का संचालन बंद कराकर परिसर शट डाउन किया गया।- टीम ने खाद्य पदार्थों के कुल 5 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त पर विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने एवं अस्वच्छ दशा में खाद्य निर्माण, भंडारण व विक्रय करने पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं कस्बा पटवारी गोपाल भाटी उपस्थित रहे।

एसडीएम नीमच श्री जैन ने तीन निजी अस्पतालों का किया निरीक्षण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। एसडीएम नीमच श्री पराग जैन ने गुरुवार को राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नीमच शहर स्थित गुप्ता हॉस्पिटल, चौधरी नर्सिंग होम एवं केयर वेल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार नीमच नगर श्री संजय मालवीय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री जैन ने अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी वार्ड, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, दवा भंडार, स्वच्छता व्यवस्था, फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन एवं मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों एवं स्टाफ से मरीजों के उपचार, पंजीयन, शुल्क एवं उपलब्ध संसाधनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। एसडीएम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए? सभी आवश्यक दस्तावेज एवं अनुमतियां अद्यतन रखें तथा अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नीमच में फैटी लीवर जांच शिविर सम्पन्न

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला चिकित्सालय नीमच द्वारा ग्लोबल फैटी लीवर दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 102 मरीजों की फैटी लीवर स्क्रीनिंग एवं फॉलोअप किया गया। इस अवसर पर मरीजों को फैटी लिवर रोग के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ समय पर जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। एनसीडी नोडल अधिकारी डॉ.मनीष यादव ने शिविर में उपस्थित मरीजों को फैटी लिवर की स्क्रीनिंग, दैनिक दिनचर्या, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम तथा स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जिला चिकित्सालय नीमच में उपलब्ध फैटी लिवर से संबंधित निःशुल्क जांच सुविधाओं के बारे में भी बताया। डॉ.यादव ने बताया, कि फैटी लीवर एक साइलेंट डिजीज है, जिसके प्रारंभिक चरण में सामान्यतः कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। यदि समय रहते इसकी पहचान और उपचार न किया जाए तो यह आगे चलकर लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर एवं लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत आवश्यक है। जिला चिकित्सालय नीमच द्वारा भविष्य में भी आमजन में गैर-संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा निःशुल्क जांच एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन निरंतर किया जावेगा।

पशुपतिनाथजी मंदिर में अति शीघ्र प्रारंभ होगी भोजनशाला, श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर मिलेगा भोजन एवं नाश्ता

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर अदिति गर्ग के विशेष प्रयासों से श्री पशुपतिनाथजी मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुविधा के लिए श्री पशुपतिनाथजी मंदिर के सामने स्थित मेघदूतम-कैफेटेरिया परिसर में संचालित भोजनशाला एवं कैंटीन में विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। भोजनशाला में सामान्य भोजन थाली मात्र 60 रुपए में उपलब्ध होगी, जिसमें सब्जी, दाल, चावल, 4 रोटी, सलाद, पापड़, अचार एवं रायता शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्त विशेष भोजन के रूप में कढ़ी-चावल, दाल-चावल एवं राजमा-चावल की एक-एक प्लेट 40 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी।भोजन के साथ अतिरिक्त सामग्री के रूप में रोटी 5 रुपए प्रति नग, बटर रोटी 8 रुपए प्रति नग, पापड़ 5 रुपए तथा ग्रीन सलाद 20 रुपए में उपलब्ध रहेगा। कैंटीन में चाय 10 रुपए, कॉफी 12 रुपए, लस्सी 20 रुपए, छाछ 10 रुपए तथा दही 20 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एवं विभिन्न प्रकार के शेक एमआरपी दरों पर उपलब्ध रहेंगे। नाश्ते की श्रेणी में समोसा एवं कचोरी 10-10 रुपए, आलू पराठा 20 रुपए, खमन 30 रुपए, उपमा 40 रुपए, इडली-सांभर 50 रुपए, प्लेन डोसा 50 रुपए, मसाला डोसा 60 रुपए, पाव भाजी 60 रुपए तथा छोले भटूरे 60 रुपए में उपलब्ध रहेंगे। भोजनालय एवं कैंटीन के प्रारंभ होने से पशुपतिनाथजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं नाश्ते की सुविधाएं उचित एवं निर्धारित दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी।

नीमच जिला कृषि एवं उद्यानिकी में रच रहा नए कीर्तिमान

पीएमएफएमई–ओडीओपी में 100% ऋण स्वीकृति, प्रदेश में द्वितीय स्थान पर नीमच

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नीमच जिले ने कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों से प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) - ODOP: वर्ष 2025-26 में जिले को 134 इकाई स्थापना हेतु ऋण स्वीकृति का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध 134 प्रकरण स्वीकृत, 119 प्रकरण वितरित कर 119 इकाइयां स्थापित की गईं। 100% ऋण स्वीकृति के साथ नीमच जिला प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। जिले में ODOP योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा विश्वकर्मा हाईटेक कृषि फार्म, कन्नौरी, मालवा बाइट्स आदि ब्रांड नेम से अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार एवं अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली, मुंबई में विक्रय कर लाभ अर्जित किया जा रहा है। उप संचालक उद्यानिकीश्री अतरसिह कन्नौजी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना संरक्षित खेती- वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विकासखण्ड-जावद में शेडनेट हाउस का क्लस्टर तैयार कर कुल 41 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 1,04,375 वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट निर्माण कराया गया। इस तकनीक से किसान 2000 वर्ग मीटर में खीरा/शिमला मिर्च की खेती कर 4-5 लाख रुपये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शेडनेट निर्माण लागत 710/- प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत (355/- प्रति वर्गमीटर) अनुदान दिया जाता है। संरक्षित खेती के क्लस्टर विकास में नीमच जिला संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।- सब्जी/मसाला क्षेत्र विस्तार- MIDH/राज्य योजना अंतर्गत लक्ष्य 370.00 हेक्टेयर के विरुद्ध 100% पूर्ति कर 530 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना योजना घटक पर ड्रॉप, मोर क्रॉप अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 612.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई कार्य संपादित कर 624 कृषकों को लाभान्वित किया गया तथा दोनों वर्षों में 100% पूर्ति की गई। जिले में नवाचार, तकनीकी खेती एवं शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में सार्थक प्रगति हो रही है।

मन्दसौर से पुणे के बीच दैनिक रेल सेवा शुरू करने की उठी मांग, रेल मंत्री को भेजी चिट्ठी

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र उदिया ने भारत सरकार के केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भेजकर मन्दसौर और पुणे के बीच नियमित दैनिक रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री का ध्यान मन्दसौर जिला वासियों की एक बेहद महत्वपूर्ण जनसमस्या की ओर आकर्षित करते हुए इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है।

पत्र में बताया गया है कि वर्तमान समय में मन्दसौर और उसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न कारणों से पुणे में निवास कर रहे हैं। इन लोगों को मन्दसौर और पुणे के बीच नियमित आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच ट्रेनों की संख्या बेहद सीमित है, जो सप्ताह में केवल एक या दो दिन ही संचालित होती हैं। इन सीमित ट्रेनों में मेवाड़ हमसफर एक्सप्रेस, मडुर जंक्शन-मैसूर स्पेशल ट्रेन, उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस और यशवंतपुर से जयपुर एक्सप्रेस शामिल हैं, जो केवल साप्ताहिक या सप्ताह में बेहद सीमित दिनों के लिए ही उपलब्ध हैं। रेलवे सेवाओं की इस भारी कमी के कारण यात्रियों को लंबी वेटिंग सूची, टिकट कन्फर्म न होने की समस्या, अधिक खर्च वाले वैकल्पिक साधनों का उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यधिक मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। त्योहारों एवं छुट्टियों के समय यह समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र उदिया ने रेल मंत्री से विनम्र अनुरोध किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और मन्दसौर से पुणे के बीच नियमित दैनिक रेल सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाए। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से मन्दसौर जिले के हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों एवं कामकाजी लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इस मांग की प्रतिलिपि मन्दसौर के राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

भूतेश्वर महादेव मंदिर निर्माण को मिली गति, जमीन व 7 लाख रुपये का दान घोषित नई कार्यकारिणी गठित, भव्य मॉडल व नक्शा प्रस्तुत, 22 जून को होगी अगली बैठक

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भूतेश्वर महादेव मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर गुरुवार को मंदिर परिसर में निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर निर्माण की मुख्य कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री महाकाल और जय श्री भूतेश्वरनाथ के जयघोष के साथ मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। बैठक में मंदिर निर्माण समिति की नई कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें महेश तिवारी को अध्यक्ष, सुनील सोनी को उपाध्यक्ष, कमल शर्मा को कोषाध्यक्ष, हंसराज खटीक को सह-कोषाध्यक्ष, राजेश नागोरी को सचिव तथा मदनलाल धाकड़ (फोरु) को सहसचिव बनाया गया। मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहयोग की घोषणा की। राजेश लोहार ने मंदिर से सटी 15म120 फीट भूमि दान देने की घोषणा की। वहीं महेश तिवारी, कमल शर्मा, गोविंद शर्मा, मोतीलाल धाकड़, शंकर लक्ष्यकार, दिनेश ठेकेदार और देवीलाल गुर्जर ने एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। कन्हैयालाल जंगम ने 151 सीमेंट के बोरे देने का संकल्प लिया। इसके अलावा 21 हजार रुपये की रसीदें भी प्राप्त हुईं। बैठक के दौरान मंदिर का प्रस्तावित भव्य मॉडल और नक्शा भी प्रदर्शित किया गया। प्रस्तावित योजना के अनुसार लगभग 200 फीट लंबे परिसर में 25म15 फीट का मुख्य मंदिर, लिफ्टयुक्त कक्ष, तुलसी क्षेत्र, स्विमिंग पूल सहित बाउंड्री वॉल तथा चारों ओर आकर्षक लैंडस्केप गार्डन विकसित किया जाएगा। मॉडल में दो कुंड, हरियाली से युक्त परिसर और रात्रिकालीन रोशनी की विशेष व्यवस्था दर्शाई गई।

मंदिर निर्माण कार्य को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए मंदिर निर्माण समिति और चंदा समिति का भी गठन किया गया। बैठक में उपस्थित सर्वसमाज के श्रद्धालुओं ने जमीन पर बैठकर एकजुटता का परिचय दिया तथा विभिन्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की। कार्यकारिणी के विस्तार एवं आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए अगली बैठक 22 जून 2026 को सायं 7-15 बजे विवेकानंद बाजार स्थित गौतमालय भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का संकल्प लिया।

एमआरपी के नाम पर ग्राहकों की हो रही लूट के विरुद्ध ग्राहक पंचायत का 12 जून को जंतर-मंतर पर विशाल धरना

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लंबे समय से देश के सर्वसाधारण ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। संगठन का मानना है कि वर्तमान में अनेक स्थानों पर ग्राहकों से अधिकतम खुदरा मूल्य के नाम पर अनुचित वसूली की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। ग्राहक पंचायत लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि एमआरपी संबंधी एक स्पष्ट, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी नीति बनाई जाए, ताकि ग्राहकों के साथ होने वाली अनियमितताओं और भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जा सके। इस मांग को लेकर संगठन द्वारा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान एवं आंदोलन संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा 12 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन में देशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रमुखता से रखेंगे। इस धरना-प्रदर्शन में महू तथा इंदौर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर भागीदारी करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने सभी ग्राहक हितैषी नागरिकों से इस जनआंदोलन को समर्थन देने एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

मल्हारगढ़ में पुतला दहन, घेराव कर सौंपा ज्ञापन, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई नोक-झोंक, वाहन के कांच टूटने से बढ़ा तनाव

किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं ने लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा की उठाई मांग

मंदसौर। राज्यसभा चुनाव में मन्दसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में गुरुवार को मल्हारगढ़ में व्यापक जनआंदोलन दे टीखने को मिला। किसान नेता श्यामलाल जोकचंद एवं कमलेश पटेल के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र भर से किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, युवा और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए सरकार और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। सुबह से ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग मल्हारगढ़ पहुंचने लगे थे। दोपहर तक गाडगिल चौराहा प्रदर्शनकारियों से भर गया। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बताया। सभा के दौरान लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और निष्पक्ष चुनाव कराओ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

गाडगिल चौराहे पर फूंका पुतला- विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का चकमा देकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर दिया । पुतला दहन के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर तक खींचतान की स्थिति भी बनी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा रहा।

रैली निकालकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय- सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने गाडगिल चौराहे से एसडीएम कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। रैली में शामिल लोग हाथों में बैनर, तख्तियां और झंडे लिए हुए चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मार्ग में नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग उठाई। रैली के कारण नगर के प्रमुख मार्गों पर काफी देर तक राजनीतिक माहौल गर्म बना रहा। एसडीएम कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव किया तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में राज्यसभा नामांकन निरस्तीकरण मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। संचालन दिनेश कारपेंटर ने किया। इशू धनगर ने आभार माना।

लोकतंत्र पर हमला बताया नामांकन निरस्तीकरण- सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता श्यामलाल जोकचंद ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में एक योग्य, शिक्षित और संघर्षशील महिला नेता को राजनीतिक दबाव के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होगा। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता और लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए।

किसानों की समस्याओं को भी उठाया- जोकचंद ने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सहकारी संस्थाओं और सोसायटियों में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की संस्थाओं पर राजनीतिक कब्जा होने के कारण किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी चुनाव पिछले लगभग 15 वर्षों से नहीं कराए गए हैं, जिससे किसानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिल रहा है।

'महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ा मुद्दा- कमलेश पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सम्मान का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर होता है तो लोकतंत्र की नींव भी कमजोर हो सकती है।

पुतला दहन के दौरान बढ़ा तनाव- प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पुतला दहन के दौरान हुई अफरा-तफरी में रीछा के पूर्व सरपंच धर्मेंद्र धनगर की कार के कांच टूट गए। वहीं खींचतान के दौरान नारायणगढ़ के पूर्व पार्षद सुनील दिवानिया के गाल पर चोट लगने की जानकारी भी सामने आई। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ गया और तहसील कार्यालय परिसर में पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हुई। किसान नेता श्यामलाल जोकचंद ने क्षतिग्रस्त वाहन की भरपाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन को खरी-खोटी सुनाई।

आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला- जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा वाहन को अपने कब्जे में ले लिया गया था। इस पर प्रदर्शनकारियों ने वाहन को मौके पर लाने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की। प्रारंभ में थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी ने क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस पर असहमति जताई। बाद में पिपलिया मंडी थाना प्रभारी विक्रमसिंह इवने द्वारा क्षतिग्रस्त कांच की राशि दिलाने का भरोसा दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश शांत हुआ और स्थिति सामान्य हो सकी।

कांच नही टूटा, आरोप गलत- मल्हारगढ़ टीआई अनिल रघुवंशी का कहना है कार में पुतले लाए गए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। कांच टूटने का आरोप गलत है।

सम्पादकीय

नए किस्म के पर्यावरणवाद की आवश्यकता, क्यों टिकाऊ विकास की शुरुआत समावेशिता से होनी चाहिए?

हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वर्ष जब मैं यह आलेख लिख रही हूं मेरा शहर दिल्ली जल रहा है। यह एक जीवित अग्निकुंड बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ते तापमान का कारण जलवायु परिवर्तन है। यह अब निर्विवाद है। लेकिन हमारे शहरों के निर्माण के तौर तरीके भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

उदाहरण के लिए कंक्रीट का बढ़ता उपयोग, सड़कों पर वाहनों से निकलने वाली गर्मी और कमरों में एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी भी तापमान बढ़ाने की वजह है। हम बिना इन्सुलेशन, वेंटिलेशन या तेज धूप से बचाने वाले शेडिंग के निर्माण कर रहे हैं। इन सबके साथ-साथ पेड़ों और जलस्रोतों द्वारा मिलने वाली प्राकृतिक ठंडक का अभाव भी गर्मी को बहुत भीषण बना देता है। प्राकृतिक ठंडक के खत्म होने में निर्माण गतिविधियों में तेजी भी एक वजह है।

अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण बनाम विकास की निरर्थक बहस को किनारे रखें। हमें पता है कि मनुष्यों ने ही जलवायु परिवर्तन को आज की इस महाविपत्ति में बदला है और हमने यह सब विकास के नाम पर किया है। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाला उत्सर्जन जो आर्थिक वृद्धि, आजीविका और कल्याण के लिए आवश्यक है, तापमान में इजाफा कर रहा है और मौसम प्रणालियों को अनियंत्रित कर रहा है।

यही विकास का मॉडल आज सवालों के घेरे में है। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है। इसलिए चुनौती यह है कि हम विकास के तरीके को बदलें न कि बहस को एक निरर्थक विकास विरोधी के स्वरूप में सीमित कर दें। जब यह स्पष्ट हो जाए तब हम अगले मुद्दे पर जा सकते हैं कि देश किस तरह स्थानीय प्रदूषण समस्याओं को दूर करने के बावजूद वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में योगदान करते रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। जैसे कि भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाला कचरा और पर्यावरण के अनुकूल बदलाव के लिए नए खनिजों की बढ़ती मांग। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन अनसुलझा ही रहता है भले ही आकाश नीला हो और पानी साफ नजर आए। यह हमें बताता है कि हर देश को पर्यावरणवाद के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पुराने तरीके अब कारगर नहीं हैं और उनके लिए बहुत देर हो चुकी है।

दशकों के काम ने हमें कुछ अहम सबक सिखाए हैं। पहला, टिकाऊ विकास तब तक संभव नहीं है जब तक विकास समावेशी और सुलभ न हो। भारत की बात करें तो हम जानते हैं कि जब तक हम सभी को आवागमन की सुविधा नहीं देंगे तब तक हमारे पास स्वच्छ हवा नहीं होगी, जब तक सभी के लिए स्वच्छता नहीं होगी तब तक हमारी नदियां प्रदूषणमुक्त नहीं होंगी और ऐसी ही कुछ अन्य चीजें। हमें यह भी पता है कि केवल तकनीकी दृष्टिकोण समस्या का समाधान नहीं करेंगे। पर्यावरण तभी सुधरेगा जब विकास सभी के लिए काम करेगा। जिसमें गरीब भी शामिल हों।

दूसरा, हम जानते हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। हम उन्हें कैसे निकालते हैं और उनसे अर्थव्यवस्था कैसे बनाते हैं। यह पुराने कोयला-गैस अर्थतंत्र पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि नए हरित अर्थतंत्र पर जिसमें सौर पैनल और बैटरियां शामिल हैं और जिसके लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्खनन आवश्यक है। यह नए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अर्थतंत्र पर भी लागू होता है जिसे पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

पिछले दशकों में हमने इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। हमने कुछ हद तक सीखा है कि मत्स्य पालन, खनन या वन प्रबंधन को अधिक टिकाऊ कैसे बनाया जाए लेकिन प्रगति सीमित रही है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इन संसाधनों के मालिक समुदायों के साथ लाभ कैसे साझा किया जाए। हम बस उनके संसाधन ले लेते हैं और उन्हें और गरीब बना देते हैं। आने वाले दशक में इस शक्ति असंतुलन को ठीक करना होगा ताकि स्थायित्व हासिल की जा सके। तीसरा, पर्यावरणवाद का संबंध संस्थाओं से भी है जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों के बीच और उद्योग या कृषि की जरूरतों तथा समुदायों के अधिकारों के बीच इस संतुलन को ला सकती हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में है जो उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान से प्रेरित हो। यह जवाबदेह और पारदर्शी संरचनाओं के बारे में है जो हमें विकास की लागत समझने की अनुमति दें। लेकिन यहीं पर हम वास्तव में गलत रास्ते पर चले गए हैं। हमने शासन, नियमन और निगरानी की संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और यही कारण है कि हम आज इस स्थिति में हैं। अब पर्यावरणीय चुनौती हर उस चीज पर मंडरा रही है जिसे हम महत्त्व देते हैं। कृषि को उत्पादक बनाना होगा लेकिन साथ ही टिकाऊ भी और किसानों के हाथों में पैसा पहुंचाना होगा। गरीबों की अर्थव्यवस्था बनानी होगी ताकि वे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक बन सकें। जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी चाहे सूखा हो या जलवायु संबंधी तनाव। हमें ऐसे विकास मार्ग भी खोजने होंगे जो प्रदूषण के बिना विकास को नए सिरे से तय कर सकें और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकें। अच्छी खबर यह है कि आज हम पहले के किसी भी विश्व पर्यावरण दिवस की तुलना में अधिक जानते हैं कि हमें क्या अलग करने की आवश्यकता है।

शांति एवं आनंद का वास्तविक व स्थायी स्रोत

सहजयोग एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और आंतरिक शांति, आनंद तथा संतुलन का अनुभव प्रदान करती है। मानव जीवन की प्रत्येक खोज के पीछे आनंद की तलाश छिपी होती है। व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान या भौतिक सुखों में संतोष खोजता है, परंतु उसे स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। जब वह बाहरी संसार में भटककर थक जाता है, तब उसका ध्यान अध्यात्म की ओर जाता है। सहजयोग यही समझाता है कि जिस आनंद की खोज मनुष्य बाहर कर रहा है, वह वास्तव में उसके भीतर ही विद्यमान है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव, अपने प्रेम, सौंदर्य और आत्मिक शक्ति से अपरिचित होने के कारण बाहरी वस्तुओं में सुख ढूँढ़ता रहता है। सहजयोग के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर व्यक्ति अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना को अनुभव कर सकता है, जो शांति और आनंद का असीम स्रोत है। यह मार्ग किसी जटिल तपस्या या कठिन साधना पर आधारित नहीं है, बल्कि सहज और स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सहजयोग हमें सिखाता है कि परमात्मा का अनुभव केवल विचारों, तर्कों या पुस्तकों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करके किया जा सकता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व की गरिमा, शांति और प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इस प्रकार सहजयोग बाहरी खोजों से भीतर की यात्रा की ओर ले जाकर मनुष्य को स्थायी आनंद, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उत्कर्ष प्रदान करता है।

सहजयोग हमें स्वयं से जुड़ने, विचारों के भ्रम से ऊपर उठने और परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने का सरल मार्ग प्रदान करता है। यह केवल एक ध्यान पद्धति नहीं, बल्कि आत्म-जागरण और आत्म-परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, करुणा, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति लाती है। इसलिए सहजयोग आधुनिक जीवन की अशांति और तनाव के बीच एक ऐसा प्रकाशस्तंभ है, जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराकर स्थायी आनंद और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है।

बचपन की मिठास को कड़वे पसीने में बदलती यह निर्दयी दुनिया

किसी भी समाज का भविष्य बच्चों की आँखों में बसता है। जब उन आँखों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुँचने से पहले ही श्रम की धूल में खो जाएँ, जब नन्हे हाथ खिलौनों और किताबों के बजाय बोझ और औजार उठाने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मानवता हार रही है। 12 जून का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इसी पीड़ा की याद दिलाता है—यह उन करोड़ों बच्चों की मौन पुकार है जिनसे उनका बचपन छिन गया। तकनीकी युग में भी असंख्य बच्चे श्रम की बेड़ियों में जकड़े हैं। किसी राष्ट्र की सच्ची समृद्धि उसके सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक बचपन से मापी जाती है; बचपन असुरक्षित हो तो विकास फीका पड़ जाता है।

आँकड़े बताते हैं कि बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई अभी अधूरी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भी दुनिया के लगभग 138 मिलियन बच्चे बाल श्रम में फँसे हुए थे, जिनमें 54 मिलियन बच्चे ऐसे खतरनाक कार्य कर रहे थे जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सीधा खतरा हैं। निस्संदेह, वर्ष 2000 के 246 मिलियन की तुलना में यह संख्या लगभग आधी हुई है, पर संतोष का कोई कारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 8.7, जिसके तहत 2025 तक बाल श्रम समाप्त करने का संकल्प था, पूरा नहीं हो सका। प्रयासों ने तस्वीर बदली है, लेकिन हकीकत नहीं; जब तक आखिरी बच्चा भी श्रम से मुक्त नहीं होता, तब तक हर उपलब्धि अधूरी रहेगी।

बाल श्रम का वैश्विक भूगोल भी गहरी चिंता पैदा करता है। उप-सहारा अफ्रीका में लगभग 87 मिलियन बच्चे बाल श्रम में फँसे हैं, जो विश्व के कुल बोझ का लगभग दो-तिहाई है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संख्या 49 मिलियन से घटकर 28 मिलियन हुई है, पर राहत अभी अधूरी है। आज भी लगभग 61 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। खेतों, बागानों और पशुपालन में खपते इन बच्चों के श्रम का हिसाब मिलता है, लेकिन उनके खोए बचपन का नहीं। घरेलू काम, छोटे कारखाने, बाजार, निर्माण स्थल और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ भी बाल श्रम के छिपे केंद्र बने हुए हैं। विडंबना यह है कि हम उत्पादों की चमक देखते हैं, पर उनके पीछे खोया बचपन नहीं।

भारत की स्थिति किसी भी तरह के आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं छोड़ती। आधिकारिक आँकड़ों में लाखों बच्चे बाल श्रम में दर्ज हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे इससे कहीं अधिक मानते हैं। कृषि, पटाखा, चमड़ा, काँच उद्योग, खदानें और शहरी घरेलू कार्य—हर जगह बचपन श्रम में उलझा दिखता है। महामारी के बाद बढ़ी गरीबी, मानव तस्करी, पारिवारिक मजबूरियाँ और जलवायु संकट ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज श्रम में खोया हर बच्चा कल की प्रतिभा हो सकता था। बाल श्रम दरअसल भविष्य की संभावनाओं की चोरी है। कानून मौजूद हैं, पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी कमजोर है—एफआईआर बढ़ती हैं, लेकिन दोषसिद्धि कम।

बाल श्रम केवल अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की नैतिक परीक्षा है। एक ओर हम बच्चों को देवतुल्य मानकर पूजते हैं, दूसरी ओर वही व्यवस्था उन्हें सबसे सस्ता श्रमिक बना देती है। गरीबी, अशिक्षा, वयस्कों के लिए रोजगार की कमी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा—ये चार आधार बाल श्रम को मजबूती देते हैं। आजीविका के दबाव में परिवार बच्चों को भी श्रम की ओर धकेल देते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, संघर्ष और युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियाँ उनके बचपन को और संकुचित कर रही हैं। स्पष्ट है कि समाधान केवल बच्चों को काम से हटाने में नहीं, बल्कि उन सामाजिक-आर्थिक कारणों को बदलने में है जो उन्हें वहाँ पहुँचाते हैं।

बाल श्रम के विरुद्ध अभियान में वर्ष 2026 का विषय निर्णायक संकेत देता है—÷बाल श्रम को लाल कार्ड÷ बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक कार्य।÷ यह केवल नारा नहीं, बल्कि नीति परिवर्तन का आह्वान है। इसका स्पष्ट संदेश है कि बच्चों को अवसर और वयस्कों को सम्मानजनक रोजगार साथ-साथ दिए बिना बाल श्रम समाप्त नहीं होगा। फरवरी 2026 की माराकेश रूपरेखा ने भी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुधार पर जोर दिया है। लेकिन संकल्प तभी सार्थक हैं जब वे जमीन पर बदलाहट बनें। दुनिया ने बाल श्रम के विरुद्ध अनेक संकल्प लिए हैं; अब जरूरत घोषणाओं से आगे बढ़कर उन्हें लागू करने की है।

बाल श्रम केवल अधिकारों का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानव विकास की गहरी बाधा है। बचपन में काम करने को मजबूर बच्चा शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाता है, जिससे आगे उसकी आय, अवसर और उत्पादकता सीमित हो जाती है और गरीबी पीढ़ियों तक चलती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादकता, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता पर भी पड़ता है। फिर भी आशा बनी हुई है—कुछ गाँवों की सामुदायिक निगरानी, एनजीओ की पहल और राज्य स्तरीय योजनाएँ सकारात्मक संकेत दे रही हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं; जरूरत है एक व्यापक, सख्त और समन्वित अभियान की, जिसमें पारदर्शी आपूर्ति शृंखलाएँ, कानून, आर्थिक सहारा और सामाजिक जागरूकता साथ चलें।

सभ्यता की असली पहचान बच्चों की हँसी में है, न कि उनके श्रम में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें याद दिलाता है कि अब संवेदना नहीं, निर्णायक कार्रवाई का समय है। बाल श्रम को हर स्तर पर वास्तविक ÷लाल कार्ड÷ दिखाना होगा—यह जिम्मेदारी सरकार, समाज, उद्योग और हर नागरिक की है। घर से लेकर कार्यस्थल तक यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बच्चे का श्रम हमारी सुविधा न बने। बाल श्रम से मुक्ति केवल बच्चों की नहीं, पूरी मानवता की मुक्ति है। यदि बचपन अंधेरे में खोया रहा, तो भविष्य भी अधूरा रहेगा। बच्चों को शिक्षा, खेल और सपने तथा वयस्कों को सम्मानजनक काम—यही संतुलन मानवता की असली जीत है।

-प्रो. आरके जैन

प्राथमिकता ऋण ढांचे की हो समीक्षा

प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण (पीएसएल) लंबे समय तक भारत के वित्तीय समावेशन के प्रमुख उपायों में से एक था। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा जारी एक कार्यपत्र ने इस बात का मूल्यांकन किया कि क्या निर्देशित ऋण अब भी सार्थक विकासात्मक परिणाम देता है।

साल 2020 से 2025 के बीच जिला-स्तरीय त्रैमासिक आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन ने प्राथमिकता ऋण प्रवाह में तीव्र क्षेत्रीय असंतुलन की ओर संकेत किया। यह अध्ययन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 95 फीसदी से अधिक ऋण को कवर करता है। इसके मुताबिक 10 फीसदी से कम जिलों ने सभी प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का 45 फीसदी से अधिक हिस्सा प्राप्त किया। ऋण अपेक्षाकृत विकसित राज्यों और शहरीकृत जिलों में अत्यधिक केंद्रित रहा जबकि पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के बड़े हिस्से अब भी कम सेवा वाले बने हुए हैं। अध्ययन ने यह भी पाया कि जिन जिलों में पहले से पीएसएल की पहुंच सबसे कम है वहां अतिरिक्त ऋण का आर्थिक प्रभाव सबसे कमजोर रहा। दूसरे शब्दों में पिछड़े क्षेत्रों में केवल अधिक ऋण पहुंचाना अपने आप विकास उत्पन्न नहीं करता है जब तक कि वहां अधोसंरचना, संचार और प्रशासनिक क्षमता मजबूत न हो। अध्ययन के निष्कर्षों ने पीएसएल की आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण संस्थागत अंतर भी उजागर किए। लघु वित्त बैंकों ने अध्ययन अवधि के दौरान औसतन अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 100 फीसदी सीधे प्राथमिकता क्षेत्रों को दिया जबकि भारतीय स्टेट बैंक की पीएसएल में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी लगभग 26.5 फीसदी रही और उसने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) जैसे अप्रत्यक्ष साधनों पर अधिक भरोसा किया।

जो बैंक लक्ष्य से पीछे रहे उन्होंने नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) में धन लगाया जो आवश्यक अधोसंरचना को सहारा देता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सीधे पीएसएल लक्ष्यों को पार किया जबकि निजी बैंक बाजार आधारित अनुपालन तंत्रों पर अधिक निर्भर रहे।

ये तथ्य नए नहीं हैं। वर्ष 1991 की नरसिंहम समिति से ही बैंकिंग सुधार पैनल बार-बार तर्क देते रहे हैं कि कठोर निर्देशित-ऋण आदेश ऋण आवंटन को विकृत करते हैं, लाभप्रदता को कमजोर करते हैं और बैंकों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का बोझ डाल देते हैं जहां अक्सर देनदारी में चूक का जोखिम अधिक होता है।

वर्ष 2008 की रघुराम राजन समिति ने पीएसएलसी की शुरुआत के माध्यम से अधिक लचीलापन देने की सिफारिश की जिससे बैंकों को पीएसएल दायित्वों का व्यापार करने की अनुमति मिली बजाय इसके कि वे उन्हें पूरी तरह प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से पूरा करें। इसके पीछे एकदम सरल तर्क था। वह यह कि कुछ संस्थाएं कुछ खंडों की सेवा करने के लिए बेहतर तैयार होती हैं और समान अनुपालन को मजबूर करना समावेशन के बजाय अक्षमता पैदा कर सकता है।

-धनंजय राजौरा

आध्यात्मिक सनातनी ऊर्जा के अक्षय स्रोत हमारे धार्मिक ग्रंथ

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस भारतीय जनमानस का ऐसा ग्रंथ है जो लोकभाषा में धर्म, दर्शन और जीवन-मूल्यों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान राम को केवल एक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श शासक के रूप में चित्रित किया गया है। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मर्यादा, धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

इसी प्रकार हनुमान चालीसा श्रद्धा, विश्वास और आत्मबल का अनुपम ग्रंथ है। मात्र चालीस चौपाइयों में तुलसीदास ने भगवान हनुमान के अद्वितीय व्यक्तित्व, शक्ति, भक्ति और सेवा-भाव का ऐसा चित्रण किया है जो हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। जब मनुष्य भय, चिंता, निराशा या असफलताओं से घिर जाता है, तब हनुमान चालीसा का पाठ उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं। महाभारत भी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महासागर है जिसमें जीवन के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इसमें धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष का विराट चित्र उपस्थित किया गया है। भगवद्गीता, जो महाभारत का ही अमूल्य अंग है, आज विश्व के महानतम आध्यात्मिक ग्रंथों में गिनी जाती है। गीता का संदेश है कि मनुष्य को कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है।

इन ग्रंथों की महत्ता केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि सकारात्मक चिंतन, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन सफलता के प्रमुख आधार हैं। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा मनुष्य के भीतर इन्हीं गुणों का विकास करते हैं। इनके नियमित अध्ययन और पाठ से मन में आशा, संयम, धैर्य और आत्मबल का निर्माण होता है। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों में भी इन ग्रंथों से जुड़े लोग अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और आशावादी दिखाई देते हैं।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने मनुष्य को केवल भौतिक उन्नति का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि आत्मिक विकास और नैतिक जीवन का भी पथ प्रशस्त किया है। सनातन परंपरा में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से मानव समाज को दिशा, प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान की है। रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और महाभारत ऐसे ही कालजयी ग्रंथ हैं, जो केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, संस्कृति, नीति, कर्तव्य और आध्यात्मिक चेतना के महान स्रोत हैं। इन ग्रंथों ने भारतीय समाज की आत्मा को निर्मित किया है और आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, साहस, संयम तथा सकारात्मकता का संचार कर रहे हैं।

भारत के अनेक महापुरुषों ने भी इन ग्रंथों की महत्ता को स्वीकार किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि रामनाम मेरे लिए अचूक शक्ति का स्रोत है। गांधीजी के जीवन में रामचरितमानस और रामभक्ति का विशेष स्थान था। उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे, जो उनके आध्यात्मिक विश्वास की गहराई को दर्शाते हैं।

महान शिक्षाविद् और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि भारतीय धर्मग्रंथ केवल पूजा-पाठ के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए हैं। उनके अनुसार इन ग्रंथों में निहित मूल्य मानवता के सार्वभौमिक मूल्य हैं।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है। उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्रोतों से जुड़ने का संदेश दिया। हनुमानजी के चरित्र को वे शक्ति, निष्ठा और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण मानते थे। प्रख्यात संत स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि भारतीय संस्कृति की आत्मा उसके आध्यात्मिक साहित्य में बसती है। यही साहित्य मनुष्य को बाहरी संघर्षों के बीच भी आंतरिक शांति प्रदान करता है।

आज विज्ञान और तकनीक के युग में भी इन ग्रंथों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। बल्कि बढ़ती मानसिक अशांति, तनाव, अवसाद और सामाजिक विघटन के दौर में इनकी आवश्यकता और अधिक महसूस की जा रही है। जब मनुष्य अपने मूल्यों और संस्कारों से दूर होता है, तब जीवन में भ्रम और असंतोष बढ़ता है। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा उसे पुनः अपने भीतर झांकने और आत्मबल प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

इन ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मनुष्य को केवल ईश्वर से जोड़ने का कार्य नहीं करते, बल्कि उसे बेहतर इंसान बनने की शिक्षा भी देते हैं। रामचरितमानस करुणा, त्याग, सेवा, प्रेम और मर्यादा का संदेश देता है। हनुमान चालीसा निष्ठा, साहस, समर्पण और आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है। महाभारत और गीता कर्म, धर्म और न्याय की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं।

वास्तव में ये ग्रंथ भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मेरुदंड हैं। इन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी भारतीय समाज को संस्कारित किया है। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यदि नई पीढ़ी इन ग्रंथों के मूल संदेशों को समझे और अपने जीवन में उतारे, तो वह केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, नैतिक और उत्तरदायी नागरिक भी बन सकती हैं।

हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, रामायण और महाभारत सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, नैतिक शक्ति और जीवन-प्रबंधन के महान स्रोत हैं। इनका नियमित अध्ययन और चिंतन मनुष्य को आत्मबल, सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। बदलते समय में भी इनकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है, क्योंकि मानव जीवन के मूल प्रश्न आज भी वही हैं और उनके उत्तर इन ग्रंथों में आज भी उतने ही सार्थक और प्रकाशमान हैं। इन ग्रंथों की ज्योति युगों-युगों तक मानवता का मार्ग आलोकित करती रहेगी।

-संजीव ठाकुर

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्टी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन- आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्टे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है?

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है।

भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं।

विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बाल श्रम का उपयोग न हो। जो कंपनियां ऐसा करती पाई जाएं, उनके विरुद्ध कठोर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है। केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, जीवनोपयोगी कौशल दे और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। यदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी तो बच्चों को मजदूरी के लिए भेजने की मजबूरी भी कम होगी।

हमें यह भी समझना होगा कि बचपन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है; बचपन का अर्थ है सपने देखने की स्वतंत्रता, खेलने का अधिकार, सीखने का अवसर, स्नेहपूर्ण वातावरण और सुरक्षित भविष्य। जिस समाज में बच्चे मुस्कुरा नहीं सकते, वह समाज कभी वास्तविक विकास नहीं कर सकता। आर्थिक विकास की ऊंची इमारतें तब तक अधूरी हैं जब तक उनके नीचे किसी बच्चे का कुचला हुआ बचपन पड़ा हो। महान शिक्षाविद् नेल्सन मंडेला ने कहा था, ÷किसी समाज की आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।÷ यदि हम सचमुच विकसित और संवेदनशील समाज बनना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें दया का नहीं, अधिकार का विषय मानना होगा।

आज आवश्यकता है कि सरकारें बाल श्रम के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाएं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें, तस्करी और बंधुआ श्रम के नेटवर्क को ध्वस्त करें, और हर बच्चे तक शिक्षा एवं सुरक्षा की पहुंच सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह किसी भी रूप में बाल श्रम को बढ़ावा नहीं देगा और जहां भी ऐसी घटना देखेगा, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस हमें यह संदेश देता है कि बचपन को बचाना केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की रक्षा का संकल्प है। यदि हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और अवसर प्रदान कर सकें, तो वही बच्चा कल एक सशक्त नागरिक, संवेदनशील मानव और राष्ट्रनिर्माता बनेगा। सच तो यह है कि बचपन को बचाना ही भविष्य को बचाना है। जब दुनिया का हर बच्चा भय और श्रम से मुक्त होकर मुस्कुराएगा, तभी मानव विकास की यात्रा वास्तव में सार्थक कहलाएगी।

-ललित गर्ग

गजरा गियर्स के 62 श्रमिक परिवारों ने आवास अधिकारों को लेकर उठाई आवाज, निष्पक्ष जांच की मांग

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मल्हार स्मृति मंदिर परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक संस्था सभागृह में गुरूवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गजरा गियर्स प्रा. लि. से जुड़े 62 श्रमिक परिवारों ने अपने आवासीय अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग की। पीड़ित श्रमिक परिवारों ने बताया कि वर्ष 1981 में मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा गजरा गियर्स प्रा. लि. के 62 श्रमिकों को जवाहर नगर स्थित आवास आवंटित किए गए थे। श्रमिकों के अनुसार इन मकानों की राशि वर्षों तक उनके वेतन से किस्तों के माध्यम से काटी गई और निर्धारित भुगतान पूरा होने के बावजूद आज तक मकानों की रजिस्ट्री एवं वैधानिक स्वामित्व उनके नाम नहीं किया गया है।

प्रेस वार्ता में श्रमिकों ने आशंका जताई कि कंपनी प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत से इन मकानों को अन्य व्यक्तियों अथवा भू-माफियाओं को हस्तांतरित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिकों से मकानों की पूरी राशि वसूल की जा चुकी है, तो स्वामित्व अधिकार न देना गंभीर अनियमितता है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होना आवश्यक है। श्रमिक परिवारों ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में धोखाधड़ी, आर्थिक अनियमितता, आपराधिक विश्वासघात, षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार जैसे पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अधिकारों की मांग करने पर उन्हें दबाव, धमकी या जबरन बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रमिक परिवारों ने प्रशासन से मांग की कि गजरा गियर्स प्रा. लि. एवं मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, विवादित मकानों के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए तथा सभी 62 परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने मामले की जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने की भी मांग की। पीड़ित परिवारों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन एवं शासन कानून एवं संविधान की भावना के अनुरूप श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस दौरान पीडित श्रमिक परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

नन्हे कान्हा को देख झूम उठे श्रद्धालू

पटैल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा में हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। पुरूषोत्तम मास में नगर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गवली समाज के पटेल परिवार द्वारा भी श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालू उपस्थित होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। यहां गुरूवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया।

8 जून से कलश यात्रा से प्रारंभ हुई श्रीमद भागवत कथा में प्रतिदिन कथा वाचक पं. दिनेश नागर धाराखेड़ी वालों के द्वारा कथा में आ रहे श्रद्धालुओं को प्रभु की लीलाओं से परीचित करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरूवार को कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जहां नंद बाबा बने श्रद्धालू जब अपने सिर पर टोकरी में नन्हे कान्हा को लेकर कथा स्थल पहुंचे तो पूरा पांडाल श्री कृष्ण की भक्ति से झूम उठा और भक्तों ने कान्हा जी के जयकारे लगाए। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया।

आज होगी गोवर्धन पूजा, लगेगा छप्पन भोग- आयोजन समिति के महेश गवली ने जानकारी देते बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन उत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार के दिन भी श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गोवर्धन पूजा की जाएगी और 56 भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही रविवार के दिन श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम होगा। इस दिन नई सड़क गवली समाज धर्मशाला से में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसादी ग्रहण करने की अपील की है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देवास मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजिनी जेम्स बेक ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृद्धाश्रम राजोद रोड देवास में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। शिविर का संचालन एनसीडी एवं एनपीएचसीई नोडल अधिकारी देवास के डॉ. बी.आर. शुक्ला मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में कुल 42 वृद्धजनों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वृद्धजनों को न केवल उपचार उपलब्ध कराया गया, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य परामर्श देकर जागरूक भी किया गया। इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना और उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना है।

आत्मा अंतर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए 30 जून तक आवेदन करें

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। परियोजना संचालक ''आत?मा'' एम.एल. सोलंकी ने बताया कि कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ÷आत्मा÷ अंतर्गत सर्वोत्तम कृषक राज्य, जिला एवं विकासखंड के लिए 30 जून 2026 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। उन?होंने बताया कि जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार एवं विकासखण्ड स्तरीय कृषक पुरस्कार निर्धारित आवेदन फार्म विकासखंड के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर/असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर (आत्मा) एवं कृषि विस्तार अधिकारी एवं उद्यानिकी पशुपालन, मत्स्य, कृषि एवं कृषि अभियंत्रिकी विभाग से प्राप्त करें। साथ ही वर्ष 2025-26 पुरस्कार हेतु कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीकी, उपज एवं उत्पादकता के आधार पर इच्छुक कृषकों से पुरस्कार के लिए बंद लिफाफे में प्रविष्टि विकासखंड के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर/असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर ''आत्मा'' एवं उद्यानिकी पशुपालन, मत्स्य, कृषि, एवं कृषि अभियंत्रिकी विभाग को 30 जून 2026 के पूर्व प्रस्तुत करें।

नैनावद घाटी पर हुई अर्टिगा-ऑटो की टक्कर, दो लोग घायल

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में नेशनल हाईवे-52 स्थित नैनावद घाटी पर बुधवार शाम तेज रफ्तार अर्टिगा कार और लोडिंग आटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में आटो रिक्शा में सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान दिनेश पिता गिरधारीलाल और अर्जुन उम्मट के रूप में हुई है, जो दोनों ग्राम गोलवा के निवासी हैं। बताया गया कि वे अपने लोडिंग आटो रिक्शा में खाद लेकर आगर जिले के कानड़ क्षेत्र से अपने गांव गोलवा लौट रहे थे। तभी नैनावद घाटी के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही नैनावद पुलिस चौकी का दल तुरंत मौके पर पहुंचा।

7 साल की बच्ची के चेहरे पर लौटी मुस्कान, डॉक्टरों ने पसली की हड्डी से बनाया नया कान

आयुष्मान योजना के तहत नि:शुल्क हुई जटिल सर्जरी; अमलतास के डॉक्टरों ने रचा नया कीर्तिमान

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जन्म से ही एक कान के बिना पैदा हुई 7 वर्षीय मासूम बच्ची को अब नई पहचान और नया आत्मविश्वास मिला है। अमलतास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देवास के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल सर्जरी के माध्यम से बच्ची का नया कान बनाकर चिकित्सा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

संस्थान के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉ. राहुल यादव ने बताया कि यह जन्मजात कान की विकृति, जिसे चिकित्सा विज्ञान में माइक्रोटिया कहा जाता है, का एक अत्यंत जटिल मामला था। हमारी टीम ने बच्ची की छाती की पसली (रिब कार्टिलेज) से ऊतक (टिश्यू) लेकर नया कान तैयार किया और सफलतापूर्वक उसका पुनर्निर्माण किया। आधुनिक तकनीक और अनुभवी सर्जनों डॉ.राहुल यादव, डॉ. अर्पिता , डॉ. अरविन्द , डॉ. दीक्षा, डॉ .राजा के बेहतरीन टीमवर्क से की गई यह सर्जरी पूरी तरह सफल रही है. डॉ. द्वारा बताया गया कान का पुनर्निर्माण एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह पूरी प्रक्रिया कुल तीन चरणो में संपन्न होगी, जिसमें लगभग एक वर्ष का समय लगेगा। पहले चरण में पसली की हड्डी से कान का ढांचा तैयार कर उसे प्रत्यारोपित किया गया है। अगले चरणों में कान की बनावट को और अधिक प्राकृतिक रूप और गहराई दी जाएगी।

अमलतास अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। इतनी बड़ी राहत मिलने पर भावुक परिजनों ने मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार और डॉक्टरों की टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बच्ची को अब एक नई मुस्कान और बेहतर भविष्य मिल गया है। अस्पताल प्रबंधन ने भी इसे चिकित्सा जगत और संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताया।

इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता पर अमलतास ग्रुप के चेयरमैन श्री मयंकराज सिंह भदौरिया एवं प्रबंधन ने डॉक्टरों की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, जन्मजात कान विकृति से पीड़ित बच्ची को सफल पुनर्निर्माण सर्जरी के माध्यम से नया जीवन और आत्मविश्वास देना वास्तव में गर्व का विषय है। यह सफलता हमारे संस्थान की उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं, आधुनिक तकनीक और समर्पित डॉक्टरों की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। हम भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ समाज को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बायपास पर फिर हुई ट्रक कटिंग की वारदात, चलते कंटेनर से उड़ाए 12 बॉक्स

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। बायपास पर एक बार फिर बदमाशों ने चलते कंटेनर से लाखों का माल चुरा लिया। बदमाशों ने कंटेनर की सील तोड़कर वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने कंटेनर में रखे 64 में से 12 बॉक्स चुरा लिए। चालक ने इसकी शिकायत तराना थाने में की जहां से जीरो पर कायमी कर मामला मक्सी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार विनसम एक्सप्रेस इंडिया लिमिटेड का कंटेनर क्रमांक एचआर-55 एएक्स-7297 इंदौर से घरेलू सामान के 64 बॉक्स लेकर फरीदाबाद जा रहा था। कंटेनर चालक वीरेंद्र नागर अपने सहयोगी आशुल नागर के साथ 3 जून 2026 को रात करीब 1.30 बजे इंदौर से रवाना हुए थे। रात करीब 3.10 बजे मक्सी बायपास पर एक अन्य ट्रक चालक ने वीरेंद्र नागर को कंटेनर का गेट खुला होने की सूचना दी। इसके बाद रोजवास टोल प्लाजा के पास कंटेनर को रोककर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कंटेनर की सील टूटी हुई थी और अंदर रखे 64 बॉक्स में से 12 बाक्स गायब थे। यह घटना मक्सी थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके चलते तराना थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को मक्सी थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। मक्सी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक सप्ताह जारी रहेगा चुभती-जलती गर्मी का मौसम

अगले सप्ताह से मानसून आने की संभावना

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्री-मानसून की फोरी राहत ले चुके नगरवासियों को दोबारा चुभती, तपती ओर जलती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी एक सप्ताह और मौसम का यही मिजाज रहेगा। इसके बाद मानसूनी बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान कम होने लगेगा और सुबह-शाम ठंडक का एहसास होने लगेगा।

गुरूवार को भी तापमान तो कम हुआ, लेकिन उमस से लोगों का बुरा हाल हो गया। इस दिन अधिकतम तापमान 41 डिग्री से घटकर 39.7 डिग्री दर्ज किया गया तो न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री दर्ज किया गया। इस दिन आसमान पर बादल भी छाए रहे, जिससे बारिश की संभावना बन रही थी, लेकिन कुछ देर बाद आसमान साफ हो गया और तीखी धूप निकल आई, जिससे लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने लगा। न तो लोगों को बाहर चैन मिल रहा था और न ही घर में सुकून। गर्मी के कारण पंखे और कूलर भी लोगों को राहत नहीं दे पा रहे थे। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह मौसम का यही हाल रहेगा।

इंसान ही नहीं वन्यजीव भी झुलस रहे, ढूंढ रहे छांव- आसमान से बरसती आग के बीच अब इंसानों के साथ-साथ जंगली जानवर भी बेहाल होने लगे हैं और राहत की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा पहाड़ियों पर देखने को मिला, जहां तपती दोपहरी से बचने के लिए वन्यजीव संघर्ष करते नजर आए। जहां नीलगाय चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छोटे-छोटे पेड़ों और कंटीली झाड़ियों की हल्की छांव में बैठने को मजबूर हैं। खुले मैदानों में गर्मी का प्रकोप इतना अधिक है कि वन्यजीव वहां रुक भी नहीं पा रहे हैं। शाजापुर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या घने और बड़े पेड़ों की कमी है। पर्याप्त हरियाली न होने के कारण इन बेजुबान वन्यजीवों को दोपहर के समय सुरक्षित और ठंडी जगह नहीं मिल पा रही है।

अगले सप्ताह हो सकती है मानसून की एंट्री- मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि आसपास बन रहे सिस्टम से आसमान पर बादल छा रहे हैं। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। यह जरूर है कि आज या कल से तापमान जरूर कम हो जाएगा और सुबह व शाम ठंडक का एहसास होने लगेगा। इसके बाद 17 या 18 से मानसून जिले में प्रवेश करेगा और मानसूनी बारिश की शुरूआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस माह तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन इसके बाद हवाओं की दिशा और मानसून की स्थिति देखकर ही कुछ कहा जा सकता है।

भाई की मौत से दुखी बहन ने भी जहर खाकर दी जान

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के ग्राम भेरूपुरा एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने भाई की मौत के बाद सल्फास खा लिया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान ग्राम भेरूपुरा तहसील पोलायकलां निवासी सुंदरबाई पति भागीरथ सिंह (70) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुंदरबाई के भाई ने भी कुछ समय पहले सल्फास का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। भाई की मौत से सुंदरबाई मानसिक रूप से व्यथित थी। इसी तनाव के चलते उन्होंने भी सल्फास की गोली खा ली। परिजनों ने उन्हें तत्काल ग्राम भेरूपुरा से शाजापुर लाकर उपचार दिलाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पुलिस चौकी पर पदस्थ प्रधान आरक्षक पदम सिंह ने बताया कि महिला के परिजनों के अनुसार भाई द्वारा जहर खाने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। इसी वजह से उसने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

9 साल बाद धराया 10 हजार का इनामी गांजा तस्कर

पहचान छुपाकर उज्जैन में रह रहा था आरोपी, एक क्विंटल गांजे की खरीदी-बिक्री के मामले में था फरार

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। पुलिस ने गांजे की तस्करी के एक पुराने मामले में पिछले 9 साल से भाग रहे एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। इस आरोपी पर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। जो उज्जैन में पहचान छुपाकर रह रहा था। जिस पर एक क्विंटल गांजे की अवैध खरीदी-बिक्री का आरोप है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम राजेश शर्मा है जो मोहनलाल शर्मा का बेटा है। वह मूल रूप से शाजापुर जिले के कालापीपल इलाके के चाकरोद गांव का रहने वाला है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए वह लंबे समय से अपनी पहचान छुपाकर उज्जैन की साईबाग कालोनी में रह रहा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया।

एक क्विंटल गांजे की हेराफेरी का है आरोप

जानकारी के अनुसार राजेश शर्मा के खिलाफ सुनेरा थाने में साल 2017 में गांजा तस्करी का केस दर्ज हुआ था। यह पूरा मामला करीब एक क्विंटल यानी 100 किलो गांजे की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा था। इस कार्रवाई के बाद से ही राजेश गिरफ्तारी के डर से भागा-भागा फिर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम रख दिया था। पिछले करीब 9 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे इस इनामी तस्कर को पकड़ने के बाद सुनेरा पुलिस ने उसे शाजापुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इस धंधे से जुड़े बाकी लोगों का पता लगाने और कड़ी पूछताछ के लिए कोर्ट से आरोपी की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राजेश शर्मा को पूछताछ के लिए पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अंकित मुकाती, उप निरीक्षक लकड़ा, प्रधान आरक्षक अनिल यादव तथा आरक्षक राजकुमार, पुष्पेंद्र, रूपेंद्र पाल सिंह, मनोज, सुधीर यादव, तरुण यादव, गोविंद और अखिलेश भंडारी का विशेष योगदान रहा।

पहले भी भारी मात्रा में गांजा तस्करी में आ चुका है नाम- पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि राजेश शर्मा कोई नया आरोपी नहीं है, बल्कि वह गांजे की तस्करी का पुराना आरोपी है। उसके खिलाफ पहले भी अलग-अलग जिलों में नशे की तस्करी के केस दर्ज हैं। इससे पहले शाजापुर के कालापीपल थाने में उससे 15 किलो गांजा और नरसिंहपुर जिले के सुआतला इलाके में 1 क्विंटल 6 किलो गांजा पकड़ा जा चुका है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ें

आयुष मंत्रालय की पहल, 14 जून को सुबह 6:15 से 7:35 तक होगा सत्र

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के तहत समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रयास- आयुष मंत्रालय द्वारा के सहयोग से 14 जून 2026 को प्रातः 6-15 बजे से 7-35 बजे तक एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube Platform के माध्यम से एक साथ अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।

पंजीकरण प्रक्रिया- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को टोल-फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद प्रतिभागियों को सत्र का लिंक वाला WhatsApp message प्राप्त होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास वाले दिन प्रत्येक प्रतिभागी को अपने-अपने डिवाइस से व्यक्तिगत रूप से लॉग-इन करना होगा, क्योंकि सत्र में शामिल होने वाले प्रत्येक registered डिवाइस को आधिकारिक रिकॉर्ड में गिना जाएगा। एक डिवाइस पर समूह में योग करने से केवल एक ही गिनती होगी।

अपील- कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारियों, संबद्ध संस्थानों, संगठनों, योग अभ्यासकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने व्यक्तिगत उपकरणों-मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से अलग-अलग जुड़कर इस ऐतिहासिक पहल में सक्रिय भागीदारी करें और जिले से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कराएं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है। इस सामूहिक प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है।

संयुक्त कलेक्टर संभालेंगी जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर का प्रभार संभालेंगे डिप्टी कलेक्टर

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा जिला पंचायत शाजापुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा चौहान की अनुपस्थिति के कारण प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से आगामी आदेश तक जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर का संपूर्ण प्रभार संयुक्त कलेक्टर मनीषा वास्कले तथा अपर कलेक्टर का संपूर्ण प्रभार डिप्टी कलेक्टर श्री राजकुमार हलदर को जिले में इन्हें पूर्व से सौंपे गये स्वकार्यों के साथ साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा चौहान 08 जून से बिना सूचना एवं अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।

अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर चार वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 52 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चार अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 52 हजार 700 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 0041/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार पुलिस थाना जीरन द्वारा जप्त टैक्टर क्रमांक 735 FE MP14ZK8170 में बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मुकेश पिता नानुराम बावरी निवासी मनासा खुर्द पर 28750 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।

प्रकरण क्रमांक 0040/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार ग्राम विशन्या तहसील नीमच में जप्त ट्रेक्टर महिन्दा 275 DI MP44AA7556 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक भेरूलाल पिता जयसिह बंजारा निवासी बाकरोक पर 28750 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।

प्रकरण क्रमांक 0042/अ-67/2026-27- में पारित आदेशानुसार ग्राम सोनियाना में ट्रिगर क्रमांक 14741 में बिना रॉयल्टी के अवैध उत्खनन लाल मुरूम पर वाहन मालिक श्रीलाल पिता जौहर आंजना निवासी केसुंदा तहसील छोटी सादडी जिला प्रतापगढ पर 175200 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

लाइसेंसी दुकान की आड़ में गांव गांव बिक रही अवैध शराब...

नियमों को ताक पर रख गांव गांव सजे अवैध मयखाने

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देहात इलाकों में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंगवासा चौराहे पर लाइसेंसी शराब दुकान है, जिसे सरकार ने केवल दुकान से शराब बेचने का लाइसेंस दिया है। लेकिन शराब ठेकेदार ने आबकारी और पुलिस से सांठगांठ कर क्षेत्र में अवैध शराब का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा गाँव बचा होगा जहाँ अवैध शराब का अड्डा नहीं खुला है। ठेकेदार ने गाँव-गाँव अपने एजेंट बिठाकर शराब की अवैध बिक्री शुरू करवा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग को इसके बदले लाखों रुपए महीने की बंदी दी जा रही है, जिसकी वजह से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।

वर्तमान में अटावदा, अजंदा, नेवरी, चटवाड़ा, गिट्टी खदान और रावत दौलताबाद फाटा सहित कई अन्य जगहों पर खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। इन अड्डों पर शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ देखी जा सकती है, जहाँ शराब पीने के बाद शराबी आतंक मचाते हैं। प्रदेश में अहातों पर पूरी तरह रोक होने के बावजूद यहाँ खुलेआम अवैध अहाते संचालित हो रहे हैं और बैठाकर शराब पिलाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी जानकारी पुलिस और आबकारी विभाग को भी है, लेकिन शिकायत होने पर टीम केवल दिखावे की कार्रवाई करने आती है और छोटा-मोटा केस बनाकर चली जाती है। रंगवासा चौराहे से मोटरसाइकिल के जरिए तस्कर सरेआम गाँवों में शराब की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चल रहे कारोबार पर आबकारी और पुलिस आँखें मूँदे बैठी है।

अतिरिक्त प्रभार के भरोसे व्यवस्था, साहब को फोन उठाने की फुर्सत नहीं- देपालपुर में आबकारी विभाग पूरी तरह भगवान भरोसे चल रहा है। तहसील रोड स्थित आबकारी का दफ्तर बेहद पुराना और जर्जर हालत में है, जहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठता। इस असुरक्षित दफ्तर में पहले भी जब्त की हुई शराब चोरी हो चुकी है। वर्तमान में देपालपुर आबकारी की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर भगवान दास अहरवार के पास है, जिन्हें दो महीने पहले ही यहाँ भेजा गया है। लेकिन उनके पास देपालपुर का अतिरिक्त प्रभार है और मुख्य जिम्मेदारी इंदौर में होने के कारण वे यहाँ पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी गोपाल यादव पिछले 2 साल से अधिक समय से यहाँ पदस्थ हैं। यादव के कार्यकाल में कई दरोगा तक बदल गए, लेकिन वे अवैध शराब पर अंकुश नहीं लगा पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के लिए फोन करने पर भी यादव साहब फोन नहीं उठाते और क्षेत्र से गायब रहते हैं। पिछले दिनों जब देपालपुर शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोग विरोध में सड़क पर उतरे थे, तब तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर हरेंद्र घुरैया ने टीम के साथ मौके पर पहुँचकर लोगों को समझाकर मामला शांत कराया था और पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद भी सहायक जिला आबकारी अधिकारी गोपाल यादव मौके पर दिखाई नहीं दिए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बालागंज स्टेडियम दुकानदार जून माह के अंत तक सभी अपनी दुकानें संचालित करें : कलेक्टर गर्ग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर अदिति गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में बालागंज स्टेडियम के दुकानदारों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टेडियम परिसर की दुकानों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने निर्देश दिए कि जून माह के अंत तक सभी आवंटित दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों का संचालन व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो दुकानदार निर्धारित समय सीमा तक दुकान संचालित नहीं करेंगे, उनकी दुकानों के संबंध में 1 जुलाई से अन्य पात्र दुकानदारों को आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कलेक्टर ने दुकानदारों को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही समूचे परिसर के सभी कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा दुकानों के अंदर आवश्यक मरम्मत एवं रंग-रोगन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। दुकानों के बाहरी हिस्से एवं छत की मरम्मत का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार बिना किसी भय या संकोच के अपना व्यवसाय संचालित करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन उनके साथ है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। बैठक में दुकानदारों को एक समूह एवं समिति बनाकर सामूहिक रूप से कार्य करने, परिसर की साफ-सफाई बनाए रखने तथा अपनी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सक्रिय समिति के माध्यम से परिसर के विकास एवं संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि बालागंज स्टेडियम परिसर में फूड जोन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को दुकानदारों के बही-खातों के संधारण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि बालागंज स्टेडियम परिसर में कुल 76 दुकानें निर्मित हैं, जिनमें से वर्तमान में 59 दुकानें आवंटित हैं, जबकि शेष 17 दुकानों की नीलामी की जाना प्रस्तावित है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सीहोर में नदी चौराहा स्थित सीवन नदी घाट पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री सीताराम यादव, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर और श्री सुदीप प्रजापति सहित जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने घाट पर साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया।

नशे में धुत ट्रक चालक ने पुलिया की डिवाइडर में घुसाया ट्रक

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महू-नीमच हाईवे पर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। पिपलियामंडी एवं मल्हारगढ़ के बीच बापू दा ढाबा के समीप एक ट्रक चालक ने शराब के नशे में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक को पुलिया की डिवाइडर में घुसा दिया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। यदि उस समय सड़क पर अन्य वाहन या राहगीर मौजूद होते तो गंभीर दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक चालक पिपलियामंडी की ओर से मल्हारगढ़ की तरफ जा रहा था। रास्ते में वह शराब के नशे में ट्रक को लहराते हुए चला रहा था। उसकी खतरनाक ड्राइविंग को देखकर राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने इसकी सूचना मल्हारगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल-112 पर तैनात पुलिसकर्मी विशाल तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और ट्रक को रोकने का प्रयास किया। बताया जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक पुलिया की डिवाइडर में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद भी चालक की हरकतों से यह स्पष्ट हो गया कि वह अत्यधिक नशे की हालत में था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस द्वारा पूछताछ और कार्रवाई के दौरान चालक ने पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना था कि चालक जिस प्रकार वाहन चला रहा था, उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। यदि ट्रक किसी अन्य वाहन, बाइक सवार या राहगीर को टक्कर मार देता तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को मौके से हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। समय रहते की गई कार्रवाई के चलते संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मल्हारगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान झारखंड निवासी महावीर के रूप में हुई है। चालक के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ट्रक क्रमांक जेएच 02 एई 6199 को जब्ती में लेकर जांच शुरू कर दी है। रघुवंशी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

सड़क सुधरेगी, रफ्तार बढ़ेगीः करोड़ों की लागत से चमकेगी इंगोरिया-देपालपुर सड़क, निर्माण कार्य में आई तेजी

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। क्षेत्र के वाहन चालकों और ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सिंहस्थ के पहले करोड़ों रुपए की भारी-भरकम लागत से बनाई जा रही इंगोरिया-देपालपुर सड़क का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस मार्ग के बन जाने से न सिर्फ क्षेत्र का यातायात सुगम होगा, बल्कि सफर का समय भी काफी घट जाएगा।

फरकोदा से मेंढकवास तक सड़क तैयार, बढ़ी चौड़ाई- निर्माण एजेंसी जैनको इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा सड़क का काम बेहद तेज गति से किया जा रहा है। योजना के तहत फरकोदा से लेकर मेंढकवास तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सड़क को पहले की तुलना में काफी अधिक चौड़ा किया गया है, जिससे आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। सड़क चौड़ी होने के कारण अब वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में बेहद कम समय लगेगा।

बिरगोदा में काम जारी, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान- वर्तमान में बिरगोदा क्षेत्र में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जैनको इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा काम की रफ्तार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मजबूत बेस और आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही यह सड़क लंबे समय तक क्षेत्र की जनता को सेवा देगी।

ग्रामीणों ने की तारीफ- सड़क निर्माण की इस तेज रफ्तार और बेहतरीन क्वालिटी को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह है। गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद क्षेत्र को इतनी शानदार सड़क मिलने जा रही है, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। ग्रामीणों ने कंपनी के काम और प्रशासनिक मुस्तैदी की जमकर सराहना की है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान को ठेंगा, मेंटेनेंस के नाम पर एमपीईबी ढा रहा हरे-भरे पेड़ों पर कहर

नियमों को ताक में रखकर 11 व 33 KV लाइन के लिए कर दी पोल शिफ्टिंग; छंटनी की आड़ में तने से काटे जा रहे पेड़

खरगोन/ अंजू त्रिवेदी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए %एक पेड़ मां के नाम% जैसे वृहद अभियानों के जरिए आम जनता से पौधे लगाने का आह्वान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरगोन (एमपीईबी) के जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में मस्त हैं। ताजा मामला खरगोन-सनावद मार्ग का है, जहां बिजलगांव से लेकर बलवाड़ी और प्रेमनगर तक सड़क किनारे लगे दर्जनों हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से कटर मशीनों से काटा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए विभाग को सिर्फ बिजली तारों को छूने वाली टहनियों की %छंटनी% (फ्रूनिंग) करनी थी, लेकिन यहां धड़ल्ले से कटर मशीनों के जरिए पूरे के पूरे पेड़ तने से साफ किए जा रहे हैं।

मनमर्जी की पोल शिफ्टिंग, नियमों का उल्लंघन- स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि विद्युत वितरण निगम द्वारा 11 केवी एवं 33 केवी की सर्विस लाइन के लिए की गई पोल शिफ्टिंग में शासन के तय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। बिना किसी ठोस योजना और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के, ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी से पोल खड़े कर दिए। अब इन पोल और तारों को बचाने के लिए रास्ते में आने वाले सालों पुराने छायादार और फलदार पेड़ों की बली चढ़ाई जा रही है।

मशीनों से बेखौफ काटा जा रहा पर्यावरण का गला- सड़क किनारे से गुजरने वाले राहगीर व पत्रकार दिलीप पंचोली ने बताया कि मानसून पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर चल रहे इस खेल में पर्यावरण नियमों को पूरी तरह ताक में रख दिया गया है। कायदे से बिजली कंपनी को केवल उन डालियों को काटना होता है जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो, परंतु विभागीय शह पर बेखौफ होकर कटर मशीनों से हरे-भरे पेड़ों को जमींदोज किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। जब सरकार पेड़ लगाने की बात कर रही है, तब सरकारी महकमा ही मशीनों से पेड़ काट रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

स्थानीय नागरिक एवं पर्यावरण प्रेमी उठा रहे हैं कई गंभीर सवाल-

सवाल 1- क्या विद्युत विभाग ने पोल शिफ्टिंग और पेड़ काटने के लिए राजस्व विभाग तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी संबंधित स्थानीय प्रशासन से नियमानुसार अनुमति ली थी?

सवाल 2- मेंटेनेंस के नाम पर टहनियां काटने का आदेश था या आधे तना तक पूरे पेड़ काटने की खुली छूट दी गई थी?

सवाल 3- शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर की गई पोल शिफ्टिंग पर अब तक वरिष्ठ अधिकारियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? विभागीय अधिकारियों की इस तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ अब क्षेत्र के नागरिकों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस अवैध कटाई को तुरंत रोका जाए, प्रकृति को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए और संबंधित गैर-जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने आष्टा जनपद के खाद वितरण केंद्रों एवं फार्मर आईडी कैंप का किया निरीक्षण

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने आष्टा, कोठरी, ग्राम डाबरी और पगारिया राम में सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे खाद वितरण कार्य, फार्मर आईडी कैंप, समिति कार्यालयों तथा किसानों के लिए संचालित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद लेने पहुंचे किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सहकारी समितियों में संचालित ई-टोकन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की तथा किसानों से चर्चा कर व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया।

उन्होंने कहा कि किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े और खाद विक्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, सुचारु एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाए और किसानों को ई टोकन के माध्यम से पात्रतानुसार एवं नियमानुसार ही खाद प्रदान किया जाए।कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने खाद के उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया तथा गोदाम का निरीक्षण कर भंडारण व्यवस्था देखी। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-विकास पोर्टल पर दर्ज खाद स्टॉक एवं गोदाम में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए।

बिना किसी उचित कारण के लंबित न रखे जाएं आवास योजना के आवेदन - कलेक्टर

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), नगरीय निकायों तथा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित विभागों की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले में स्वयं सहायता समूहों का दायरा बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक महिलाओं को समूहों से जोड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि समूहों की गतिविधियों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण के आवास संबंधी आवेदन लंबित न रखे जाएं तथा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति एवं निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने 12, 15 एवं 16 जून को आयोजित होने वाले जनकल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मनरेगा के तहत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने रोजगार सृजन के कार्यों में गति बनाए रखने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा योजना के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

21 जून को उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को प्रदेशभर में व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "Yoga for Healthy Ageing (स्वस्थ आयु के लिए योग) निर्धारित की गई है। योग को जन-जन तक पहुंचाने तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रातःकाल सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रमों में आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया जाएगा।

योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार गतिविधियां संचालित की जाएंगी तथा नागरिकों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में 12 जून से 20 जून 2026 तक योग प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

मानवाधिकार सुरक्षा संघ कि प्रादेशिक बैठक एवं रोजगार मेला ओंकारेश्वर हुआं सम्पन्न

मानवाधिकारों कि सुरक्षा संकल्प सहित महेश्वर परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा देने की उठी मांग

खरगोन/ अंजू त्रिवेदी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। खरगोन-खंडवा, ओंकारेश्वर कि पावन नगरी में मानवाधिकार सुरक्षा संघ कि बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। जहां मानवाधिकारों की रक्षा, हम सबका संकल्प के मूल ध्येय को लेकर देश और प्रदेश में निरंतर सक्रिय राष्ट्रव्यापी संगठन मानवाधिकार सुरक्षा संघ के तत्वावधान में बुधवार 10 जून 2026 को धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर के शिव कोठी (ओम नमः शिवाय मिशन ट्रस्ट) में एक भव्य प्रादेशिक बैठक, सदस्य सम्मान समारोह एवं रोजगार मेले का गौरवपूर्ण आयोजन किया गया। इस समागम में संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर मध्यभारत, मध्य प्रदेश, विभिन्न संभागों, जिलों और तहसीलों के शीर्ष पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

मानवाधिकारों की रक्षा और संगठन की मजबूती पर मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य व्यवस्थाओं के तहत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और आरती के साथ हुआ। जहां खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पंचोली द्वारा मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, राष्ट्रीय गीत के माध्यम से शमां बांध दिया।

बैठक के मुख्य सत्र में मानवाधिकार सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन (गुरुजी) हारित हरिश्चंद्र जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री हनीफ पठान जी ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात पर विशेष बल दिया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, शोषितों को न्याय दिलाना और प्रशासनिक स्तर पर उनकी आवाज को बुलंद करना है।

इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सतीश गांगले जी ने मध्यभारत और मध्य प्रदेश में संघ के बढ़ते प्रभाव की रूपरेखा रखी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष इंजी.राधेश्याम पाटीदार और प्रदेश उपाध्यक्ष कमल गांगले सहित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित सभी वक्ताओं ने संगठन की वैचारिक मजबूती और आगामी समय में मानव अधिकार जागरूकता अभियान को हर गाँव-शहर तक ले जाने की कार्ययोजना साझा की।

डूब प्रभावितों के मानवाधिकारों के लिए उठी बुलंद आवाज - मानवाधिकार सुरक्षा संघ हमेशा से ही जनता के बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्षरत रहा है। इसी कड़ी में, संघ की खरगोन इकाई द्वारा ओमकारेश्वर के एक रोटी आश्रम में एक विशेष आपात बैठक भी आयोजित की गई बैठक में माँ नर्मदा विकास संगठन, खरगोन के माध्यम से श्री रामेश्वर जी पाटीदार (सुलगाँव) ने 400 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर से प्रभावित हजारों नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन का गंभीर मुद्दा उठाया। प्रभावितों के हक में संघ की प्रमुख मांगें-पुनर्वास और मुआवजे का अभावन-पिछले 27-28 वर्षों से लंबित इस परियोजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन 20 प्रतिशत काम रुका हुआ है। परियोजना के कारण डूब में आए 940 परिवारों को रेवेन्यू भूमि में आवास होने का हवाला देकर आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जो सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है।

बुनियादी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण- प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पक्की नाली, खरंजा निर्माण, नल-जल योजना, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत मानवीय सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पलायन का दंश- बुनियादी सुविधाएँ और स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों और युवाओं को अन्य राज्यों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

मानवाधिकार सुरक्षा संघ के पदाधिकारियों और डूब प्रभावित ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र पूर्ण कर प्रभावितों को तुरंत मुआवजा और बुनियादी हक दिए जाएं, अन्यथा संघ इनके अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा।

सदस्य सम्मान समारोह और रोजगार मेला- संगठन की इस वृहद बैठक में जहाँ एक ओर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जांबाज सदस्यों को संघ की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं युवाओं के रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रोजगार मेले का भी सफल संचालन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मध्यभारत सचिव राकेश पंडिया, प्रवक्ता संजीव कुमार, प्रदेश महामंत्री शंभू प्रसाद तिवारी शहडोल, प्रदेश प्रवक्ता विष्णु प्रसाद वाघे, जिला अध्यक्ष धार से राजेंद्र पाटीदार, मंदसौर से मनोहर लाल गौर, अरुण ओटवाल तहसील अध्यक्ष सनावद, जितेन्द्र भालसे प्रदेश संगठन मंत्री,और हरदा से नर्मदाप्रसाद गौर आरिफ़ ख़ान, सम्भागीय अध्यक्ष सहित सभी जिलों व तहसीलों के सैकड़ों पदाधिकारियों एवं निष्ठावान सदस्य उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम का सफल संचालन समाजसेवी संजीव कुमार, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पंचोली मध्य प्रदेश मिडिया प्रभारी, मोहन पाटिल सेवा निवृत्त शिक्षक द्वारा किया गया एवं आभार कमल गांगले द्वारा व्यक्त किया गया।

कलेक्टर ने वर्षाकालीन आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की

सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहकर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आगामी वर्षा ऋतु एवं संभावित अतिवृष्टि, बाढ़ तथा जलभराव की परिस्थितियों को देखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को पूर्ण सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित 24म7 आपदा नियंत्रण कक्ष निरंतर सक्रिय रहें तथा बाढ़ एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पटवारियों, ग्राम सचिवों एवं मैदानी अमले को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर नदी-नालों के जलस्तर की जानकारी लेने तथा किसी भी संभावित खतरे की तत्काल सूचना नियंत्रण कक्ष को देने के निर्देश दिए गए हैं। अतिवृष्टि से होने वाली जन-धन, फसल एवं पशुधन क्षति के प्रकरणों में आरबीसी 6(4) के तहत त्वरित सर्वे एवं राहत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में नगर निकायों द्वारा नालों एवं ड्रेनेज लाइनों की सफाई, डी-वाटरिंग पंपों की उपलब्धता, पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता प्रबंधन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जलभराव की स्थिति में तत्काल कार्यवाही कर नागरिकों को राहत प्रदान की जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को राहत शिविरों की तैयारी, राशन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, मुनादी व्यवस्था तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को किसानों को जल निकासी एवं फसल संरक्षण संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा क्षति की स्थिति में संयुक्त सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने होमगार्ड विभाग को बचाव दल, मोटर बोट एवं जीवन रक्षक उपकरणों सहित पूर्ण तैयारी में रहने, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं एवं एंटी-वेनम का पर्याप्त भंडारण रखने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्षाकालीन तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर डॉ. भरसट ने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सदैव तैयार रहें तथा जन-धन की हानि को न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक सभी उपाय सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद सुश्री तनुश्री मीणा, संयुक्त कलेक्टर श्री विजय कुमार मंडलोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षयसिंह मरकाम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कॉलेजों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को होगा प्रशिक्षण

खण्डवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय के पैरा 35 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, शैक्षणिक सहायकों, अधिकारियों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 6, 7 एवं 8 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले इस प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्येक कर्मचारी को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना है, जिससे किसी भी विद्यार्थी में मानसिक तनाव, अवसाद अथवा अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रारंभिक संकेतों की समय रहते पहचान कर उसे उचित परामर्श, सहायता एवं विशेषज्ञ उपचार की दिशा में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इन प्रशिक्षणों के माध्?यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अधिक संवेदनशील, सहयोगी एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए यह ऑनलाइन प्रशिक्षण 6 जुलाई 2026 को किया जाएगा, जबकि निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए 7 जुलाई 2026 को प्रशिक्षण होगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु वर्ष 2026'27 के लिये पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना व टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना व डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु संचालित स्वरोजगार योजनाओं में जिले को वर्ष 2026 - 27 के लक्ष्य प्राप्त होकर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदक पात्रता अनुसार अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से समस्त पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना तथा संत रविदास स्वरोजगार योजना - उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं एवं सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं पर ऋण बैंक द्वारा स्वीकत हो सकेगा जिस पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमति रूप से म.प्र. शासन द्वारा देय होगा।

पात्रता मापदंड - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।

आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी कक्षा होनी चाहिए। 4. आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो 6. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलिंटियर्स का एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

120 से अधिक प्रतिभागियों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण, नशामुक्ति की शपथ लेकर अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलिंटियर्स का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को एनआरएलएम आजीविका भवन, झाबुआ में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस. बघेल ने नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू, गुटखा एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है।

उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री पंकज सांवले ने कहा कि प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि आपसी समन्वय एवं सहयोग के माध्यम से जिले में नशामुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित मास्टर वॉलिंटियर्स अपने-अपने क्षेत्रों में जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन कर अभियान को गति प्रदान करेंगे।

ब्रह्मकुमारीज संस्था की जयंती दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में मादक पदार्थों के साथ-साथ मोबाइल की लत भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार के नशों से मुक्त रहना आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल से श्री जयकुमार गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता एवं मास्टर ट्रेनर श्री रजत नागदा द्वारा प्रतिभागियों को नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, जनजागरूकता गतिविधियों एवं समुदाय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था के श्री राजेंद्र राणावत ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए शराब की लत से संघर्ष और उससे मुक्ति पाने की प्रेरणादायक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था ने उन्हें नशे की आदत छोड़ने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उनके द्वारा संस्था की गतिविधियों एवं संचालित केंद्रों की जानकारी से संबंधित पठन सामग्री भी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई गई।

प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जिला स्तरीय नशामुक्ति व्हाट्सएप समूह का गठन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को जोड़ा गया, ताकि अभियान से संबंधित सूचनाओं एवं गतिविधियों का नियमित आदान-प्रदान किया जा सके।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री पंकज सांवले द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

प्रशिक्षण में सामाजिक न्याय विभाग, पुलिस विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत, नगरीय निकायों, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वयं सहायता समूहों एवं विभिन्न अशासकीय संस्थाओं के 120 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली तथा ऑनलाइन ई-शपथ के माध्यम से भी नशा मुक्त समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया।

मिशन पोषण ज्योति बड़वानी जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 13 मोबाइल टीमें करेंगी सघन स्वास्थ्य परीक्षण

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। 12 से 18 जून तक आयोजित होंगे जनकल्याण शिविर 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और शेष बचे लोगों के शत-प्रतिशत बनेंगे आयुष्मान कार्ड 100 दिवसीय टीबी कैंपेन के तहत हॉटस्पॉट में छूटे हुए लोगों की स्क्रीनिंग कर बनाई जाएगी निक्षय आईडी बड़वानी 11 जून 2026/ कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे मिशन सुपोषित बचपन से सम्बंधित रही। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।

मिशन पोषण ज्योतिरू 13 मोबाइल टीमें करेंगी जांच बैठक में कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने बताया कि जिले में मिशन पोषण ज्योति के तहत आरबीएसके के डॉक्टरों की 13 मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें संपूर्ण जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। यह अभियान मुख्य रूप से उन बच्चों पर केंद्रित होगा, जो 2 से 3 बार पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती होने के बाद भी स्वास्थ्य में कोई सकारात्मक सुधार नहीं दिखा पाए हैं। डॉक्टरों की टीम सर्वे के दौरान ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर बच्चों के परिजनों की जानकारी, परीक्षण की तारीख, वर्तमान वजन, ऊंचाई और संभावित बीमारी का पूरा डाटा इकट्ठा करेगी। इसी डाटा के आधार पर आगामी समय में इन बच्चों की सघन निगरानी की जाएगी और काउंसिलिंग के माध्यम से उनकी सेहत में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। सभी टीमों का रूट चार्ट भी फाइनल कर लिया गया है।

12 से 18 जून तक लगेंगे जनकल्याण शिविर, बनेंगे आयुष्मान कार्ड कलेक्टर ने बैठक में सभी बीएमओ और सीएचओ को निर्देशित किया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 12 से 18 जून तक जिले के विभिन्न विकासखंडों और नगरीय निकायों में जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा शत-प्रतिशत आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाएंगे।

70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन लोगों या 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बने हैं, उनकी नवीन सूची प्राप्त कर उसे आयुष्मान आरोग्य केंद्र के बाहर चस्पा किया जाए। साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर घर-घर जाकर या शिविर के माध्यम से सभी पात्र लोगों के कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। 100 दिवसीय टीबी कैंपेन बनेगी निक्षय आईडी बैठक में जिले में चल रहे 100 दिवसीय टीबी कैंपेन की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ऐसे नागरिक जो पूर्व में वल्नरेबल काउंट नहीं हो पाए थे और जिनकी स्क्रीनिंग छूट गई थी, उन्हें चिन्हित किया जाए। स्क्रीनिंग के बाद टीबी संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए उनकी निक्षय आईडी बनाई जाए, ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने दोनों विभागों के मैदानी अमले को आपसी समन्वय के साथ पूरी संवेदनशीलता से इन अभियानों को सफल बनाने और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इस दौरान संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आरबीएसके की टीम, जिले के बीएमओ, सीएचओ सहित अन्य उपस्थित रहे।

उर्वरक वितरण में कालाबाजारी व लापरवाही अक्षम्य, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई - कलेक्टर

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में जिले में सुचारू रासायनिक खाद वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने स्पष्ट किया कि रासायनिक खाद की मांग और उपलब्धता में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने खाद की उपलब्धता और वितरण को लेकर कृषि, सहकारिता और मार्कफेड के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए गए 1. 75 प्रतिशत से कम खाद वितरण करने समितियां वितरण कार्य में प्रगति लाए। जिले में सबसे कम वितरण करने वाली सिलावद, अंजड, गवाड़ी समितियों के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सभी समितियों के प्रवर्तकों को निर्देशित किया गया है कि अगली समीक्षा बैठक तक प्रगति न दिखने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2. समस्त एसडीएम को निर्देशित गया किया है कि जिले में खाद के स्टॉक की उपलब्धता की नियमित और कड़ाई से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। 3. सिंगल सुपर फॉस्फेट का वितरण पूरी तरह सुचारू और व्यवस्थित ढंग से कराया जाए ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। 4. खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी या किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5. उप संचालक कृषि विभाग, सहकारिता, मार्कफेड एवं अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इंटर-सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन (समितियों के आपसी समन्वय से वितरण) पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही निजी डीलरों के पास उपलब्ध स्टॉक की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। 6. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे किसान, जिनकी कृषि भूमि अन्य जिलों की सीमा में आती है, उनके लिए राज्य स्तर से मैपिंग की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

समान नागरिक संहिता हेतु गठित समिति की बैठक में नागरिकों ने दिए सुझाव

खण्डवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा एवं डॉ. शोभा पैठणकर ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, बार काउंसिल के सदस्य, महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि तथा समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक पंधाना श्रीमती छाया मोरे, विधायक मांधाता श्री नारायण पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री के.आर. बड़ोले, के अलावा एसएन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सोमपाल सिंह, शहर काजी सैयद निसार अली, श्री रणवीर सिंह चावला सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। बैठक में सभी धर्मों एवं वर्गों के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता के सम्बंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए।

समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि देश की मजबूती के लिए जरूरी है कि एक देश, एक कानून की भावना से समान नागरिक संहिता लागू हो। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की सहमति से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकगण समान नागरिक संहिता के लिए वेबसाइट https://ucc.mp.gov.in के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने इस अवसर पर कहा कि सभी धर्मों में महिलाओं का सम्मान रहे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता का लागू होना जरूरी है। सांसद श्री पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार सभी धर्मों और सभी वर्गों पर एकसमान कानून लागू कर सभी को समान अधिकार देना चाहती है। इसी उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल ने इस अवसर पर कहा कि समान नागरिक संहिता देश की मजबूती के लिए जरूरी है। पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे ने इस अवसर पर कहा कि सरकार महिलाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाना चाहती है। समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में निश्चित ही सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु समान होनी चाहिए और सभी विवाहों का पंजीयन होना चाहिए। लोक भवन सचिवालय के जनजातीय प्रकोष्ठ में विषय विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ. दीपमाला रावत ने इस अवसर पर कहा कि जनजातीय वर्ग को भी समान नागरिक संहिता के दायरे में लाने की आवश्यकता है, ताकि इस वर्ग की महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित न रहें।

तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला में नवाचार

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने कहा मूल्य संवर्धन से बढ़ती है उत्पादों की पहचान और बाजार संभावनाएँ बड़वानी 11 जून 2026/ युवाओं में नवाचार, उद्यमिता तथा स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह के मार्गदर्शन में बड़वानी स्थित साखी रिसॉर्ट में तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार; स्टार्टअप इंडिया; जिला प्रशासन बड़वानी; जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश सेडमेप, के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई।

कार्यशाला में जिले के लगभग 250 युवा उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप की ओर अग्रसर युवाओं, विद्यार्थियों, स्वरोजगार से जुड़े प्रतिभागियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। माँ सरस्वती के पूजन-अर्चन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी के महाप्रबंधक श्री कैलाश माल तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश के जिला समन्वयक श्री अरविन्द चौहान ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय नवाचार, कौशल और उद्यमिता का युग है तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यम स्थापना के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

वेल्यू एड करना रहे लक्ष्य मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने अपने प्रेरक उद्बोधन में युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच, नवाचार और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से युवा सफल उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बड़वानी जिले में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण के ऑफलाइन तथा ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। श्रीमती सिंह ने कहा कि उत्पादों में मूल्य संवर्धन करने से उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता तथा बाजार में स्वीकार्यता बढ़ती है, जिससे उद्यमियों को बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं।

उन्होंने जिले के युवाओं द्वारा उद्यमिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों और सफल पहलों का उल्लेख करते हुए स्थानीय संसाधनों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से जोड़ने का आह्वान किया। विशेषज्ञों ने दिया मार्गदर्शन कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में श्री गौरव गोयल, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय इंदौर ने मध्यप्रदेश की उद्यमिता व्यवस्था, नवोदित उद्यमों के लिए उपलब्ध अवसरों तथा पंजीयन प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय सत्र में श्री ऋत्विक मल्होत्रा एवं श्री रोहण सिंह, स्टार्टअप इंडिया से संबद्ध अधिकारी, नई दिल्ली ने भारत में विकसित हो रहे नवाचार आधारित उद्यमों की स्थिति तथा केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों पर विस्तृत जानकारी दी। श्री हरप्रीत सिंह वरिष्ठ प्रबंधक ने 'एक जिला एक उत्पाद' योजना नई दिल्ली ने इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट पहचान और विशेष उत्पाद होते हैं।

यदि स्थानीय उत्पादों की उचित पहचान, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी विपणन किया जाए तो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। श्री मुजम्मिल कुरैशी भोपाल ने सरकारी ई-बाजार मंच के माध्यम से उपलब्ध अवसरों की जानकारी देते हुये बताया कि व्यवस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा नवोदित उद्यमों को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

महाकाल की सवारी के हाथी श्यामू के ब्लड टेस्ट से मालिक का इनकार

डॉक्टर बोले- कभी भी गिर सकता है हाथी-स्वास्थ्य जांच टीम को लौटना पड़ा खाली हाथ, केवल मल-मूत्र के नमूने लिए गए

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। भगवान महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले हाथी श्यामू की सेहत को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। गुरुवार को हाथी की स्वास्थ्य जांच और ब्लड सैंपल लेने पहुंची विशेषज्ञों की टीम को मालिक और परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। काफी देर तक चली बहस के बाद टीम बिना ब्लड सैंपल लिए वापस लौट गई। हालांकि जांच के लिए हाथी के मल और मूत्र के नमूने लिए गए हैं।

गुरुवार को इंदौर रोड स्थित साईनाथ कॉलोनी में पहुंची संयुक्त टीम में पन्ना टाइगर रिजर्व, इंदौर चिड़ियाघर और उज्जैन के पशु चिकित्सक शामिल थे। टीम का उद्देश्य हाथी श्यामू के स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाना था। मौके पर श्यामू जंजीरों से बंधा हुआ मिला।

डॉक्टरों की चिंता- पैरों में गंभीर परेशानी, चलने में खतरा- पशु चिकित्सकों के अनुसार श्यामू के पैरों में गंभीर समस्या दिखाई दे रही है। उसके पैर मुड़ने लगे हैं, जिससे उसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी की सही स्थिति और अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट बेहद जरूरी था, लेकिन विरोध के कारण यह जांच पूरी नहीं हो सकी। उज्जैन के पशु चिकित्सक डॉ. मुकेश जैन ने बताया कि श्यामू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल-1 श्रेणी का वन्यजीव है। इसलिए उसका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाथी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विस्तृत जांच आवश्यक है।

मालिक का दावा- श्यामू पूरी तरह स्वस्थ- वहीं हाथी के मालिक सरमन गिरी ने चिकित्सकों की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि श्यामू पूरी तरह स्वस्थ है। उनके पास हाथी से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और वर्ष 2006 से उसका स्वामित्व उनके नाम पर है।

सरमन गिरी का आरोप है कि कुछ लोग हाथी को यहां से हटाकर वनतारा या किसी चिड़ियाघर में भेजना चाहते हैं, इसलिए उसे बीमार बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि श्यामू वास्तव में अस्वस्थ है तो वर्ष 2016 से लगातार महाकाल की सवारी में शामिल होने की अनुमति कैसे मिलती रही।

सितंबर 2025 से जारी है विवाद- हाथी श्यामू के स्वास्थ्य और रखरखाव को लेकर सितंबर 2025 से विवाद चल रहा है। इससे पहले भी वन विभाग और विशेषज्ञों की टीमें उसका परीक्षण करने पहुंच चुकी हैं। हाथी को सुरक्षित स्थान पर भेजने की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन मालिक ने हर बार विरोध करते हुए उसे स्वस्थ बताया। अब मल और मूत्र की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही श्यामू की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले इस हाथी को लेकर प्रशासन, विशेषज्ञों और मालिक के बीच मतभेद फिर सामने आ गए हैं।

पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का खुलासा... 5 लाख का पेट्रोल-डीजल राजसात

स्टॉक में मिला भारी अंतर, 1139 लीटर पेट्रोल कम और 911 लीटर डीजल ज्यादा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पेट्रोल पंप पर अनियमितता करना संचालक को भारी पड़ गया। घट्टिया तहसील के बिछड़ौद स्थित बोडाना पेट्रोलियम पर जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए मूल्य का पेट्रोल-डीजल राजसात करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

गुरुवार को अपर कलेक्टर अत्येन्द्र सिंह गुर्जर ने सहायक आपूर्ति अधिकारी और नापतौल निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। जांच में पेट्रोल पंप के रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया।

जांच में ऐसे खुली पोल- अधिकारियों ने अचानक निरीक्षण किया तो स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक का मिलान करने पर 1139 लीटर पेट्रोल कम और 911 लीटर डीजल अधिक पाया गया। इसके अलावा पंप पर ग्राहकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क हवा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और ऑटोमेशन मशीन भी बंद मिली।

21 हजार लीटर से ज्यादा ईंधन जब्त- अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4789 लीटर पेट्रोल और 17,178 लीटर डीजल जब्त किया था। जांच के बाद पंप संचालक को मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल आपूर्ति-वितरण नियमों के उल्लंघन का दोषी माना गया।

सरकारी खाते में जमा होगी राशि- प्रशासन ने जब्त ईंधन को राजसात करने का आदेश दिया है। अब इस सामग्री के विक्रय से मिलने वाली राशि सरकारी खाते में जमा कराई जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के अन्य पेट्रोल पंप संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

जमीन सीमाकंन से पहले 2 पक्षों में विवाद, 10 घायल

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कायथा में ग्राम खारपा स्थित चापलाखेड़ी में जमीन सीमाकंन से राठौर (मालवीय) और गुर्जर पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। गुर्जर परिवार की ओर से लाठी-डंडो से हमला किया गया। राठौर परिवार के 10 सदस्य घायल हो गये। कायथा प्रधान आरक्षक मनोज वर्मा ने बताया कि राठौर परिवार राहुल पिता चैनाजी निवासी लक्ष्मीपुरा को खारपा में पट्टा मिला हुआ था। जिस पर गुर्जर परिवार ने कब्जा कर लिया था। मामला तहसील कार्यालय में पहुंचा था। जहां से सीमाकंन के आदेश जारी हुये थे। तहसीलदार और पुलिस सीमाकंन स्थल पहुंचता उससे पहले गुर्जर और राठौर परिवार वहां पहुंच गया। गुर्जर समाज के लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ने की बात पर हमला कर दिया। जिसमें राहुल के 70 वर्षीय पिता चैनाजी राठौर, संजू पिता रामचंद्र 30 साल, गोविंद राठौर 36 साल, कैलाश 40 साल, चतरबाई 65 साल, श्यामूबाई 62 साल, अरूण 30 साल, मेहरबान 35 साल, ओमप्रकाश 30 साल घायल हो गये। राहुल की शिकायत पर हमला करने वाले नटवर गुर्जर, जितेन्द्र गुर्जर, गुड्डा गुर्जर, अरूण गुर्जर, बनेसिंह गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, ईश्वर गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ मारपीट और एसटी/एससी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।

यात्रियों के भीड़ में सक्रिय बदमाश, 9 दिन में तीन वारदात

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मो पर कुछ दिनों से बदमाशों को गिरोह सक्रिय दिखाई दे रहा है, जो महिला यात्रियों को निशाना बनाकर चेन-मंगलसूत्र उड़ा रहा है। 9 दिन में तीन वारदात सामने आ चुकी है लेकिन जीआरपी और आरपीएफ वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि वारदात में महिला गिरोह शामिल है। पिपलीनाका क्षेत्र की रहने वाली हेमलता कोठारी मंगलवार को रतलाम की यात्रा करने के लिये रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 7 पर पहुंची थी। जहां साप्ताहिक ट्रेन हैदराबाद-जयपुर का इंतजार कर रही थी। इस दौरान काफी भीड़ थी, ट्रेन के आने पर महिला यात्री ने भीड़ में चढ़ने का प्रयास किया उसी दौरान उसके गले से 2 तोला वजनी सोने की चेन बदमाशों ने उड़ा दी। ट्रेन के रवाना होने के बाद आधे रास्ते में हेमलता कोठारी को चेन चोरी होने का पता चला। रतलाम पहुंचने के बाद वह वापस लौटी और जीआरपी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पिछले 9 दिनों में महिला यात्रियों के साथ तीसरी वारदात होना सामने आई है। इससे पहले रविवार को प्लेटफार्म नम्बर 2 पर नागदा-इंदौर पैसेंजर में देवास जाने के लिये चढ़ने का प्रयास कर रही अश्विनी पति अंशुल शर्मा निवासी नागदा के गले से बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर मंगलसूत्र चोरी कर लिया था। यहीं नहीं 3 जून को प्लेटफार्म नम्बर 8 पर उज्जैन की रहने वाली सरिका पति संजय सोनी के साथ वारदात होना सामने आया था। सरिका दाहोद जाने के लिये प्लेटफार्म पर खड़ी थी उसी दौरान इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। वह कोच नम्बर 5 के खड़ी थी इसी बीच यात्रियों की भीड़ में अज्ञात बदमाशों ने उसके गले से 72 हजार कीमत की चेन गले से गायब कर दी थी। 9 दिनों में जिस तरह से तीन वारदात होना सामने आई, उससे लग रहा है कि प्लेटफार्मो पर बदमाशों गिरोह सक्रिय है। मामले में जीआरपी का कहना है कि आरपीएफ की मदद से सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं वारदात में महिला गिरोह के शामिल होने की आशंका है। जिनकी पहचान के प्रयास जारी है।

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय को भेंट किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आधारित 15 खंडों की पुस्तकों का सेट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय चिंतन, राष्ट्र निर्माण और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित 15 खंडों की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रृंखला का संपूर्ण सेट गुरुवार को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन को भेंट किया गया। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की सतत् शिक्षा अध्ययनशाला में निदेशक डॉ. सुशील कुमार शर्मा और संभागीय जनसंपर्क कार्यालय के उप संचालक श्री अरुण कुमार राठौर ने यह पुस्तक सेट विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज को सौंपा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की सतत् शिक्षा अध्ययनशाला और पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला को जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित 15 खण्ड के पुस्तकों का वांग्मय शोध और जनमानस में प्रसारित करने हेतु प्रेषित किया गया जिसे अध्ययनशाला के कार्यालय में कुलगुरु प्रो अर्पण भारद्वाज ने प्राप्त किया। इस 15 खण्ड के पुस्तकों का वांग्मय कुलगुरु प्रो अर्पण भारद्वाज को सौंपते हुए संयुक्त संचालक श्री अरुण राठौर ने पुस्तक श्रृंखला की विशेषताओं, विषयवस्तु तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुस्तकों के वांग्मय के बारे में बताते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता, अंत्योदय और राष्ट्रहित के मूल्यों से प्रेरित रहा है। पुस्तक श्रृंखला में उनके जीवन दर्शन, वैचारिक दृष्टिकोण, संगठन क्षमता, राजनीतिक चिंतन तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी कड़ी में सतत् शिक्षा अध्ययनशाला के निदेशक डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने इस 15 खण्ड के पुस्तकों के वांग्मय पर कहा कि यह पुस्तक श्रृंखला विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। विद्यार्थियों को भारतीय विचार परंपरा, राजनीतिक चिंतन और सामाजिक सरोकारों को समझने के लिए प्रामाणिक साहित्य की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक संग्रह उस आवश्यकता की पूर्ति करेगा तथा शोध और थीसिस कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराएगा। इस 15 खण्ड के पुस्तकों के वांग्मय के लेखक पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री महेश चंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने वर्षों के अध्ययन और शोध के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं कार्यों का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया है।

निर्माणाधीन सिक्स लेन सड़कों की अचानक खुदाई कर संभाग आयुक्त ने कराई जांच

बोले- गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए आज सुबह संभाग आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। नियमित निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की मौके पर खुदाई कराकर गुणवत्ता की जांच कराई।

गुरुवार सुबह संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने नानाखेड़ा चौराहा तथा लालपुल-भूखी माता-मुरलीपुरा मार्ग पर बन रही सिक्स लेन सड़कों के विभिन्न हिस्सों से नमूने लेकर उनकी परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करवाई गई।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क का एक हिस्सा खुदवाकर उसमें उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कराया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध मशीनों व परीक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क, ब्रिज, मार्ग चौड़ीकरण, घाट निर्माण सहित सभी विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की नियमित जांच कराई जाए।

आयुक्त सिंह ने अधिकारियों को प्रतिदिन जांच रिपोर्ट तैयार रखने और निर्माण सामग्री की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिंहस्थ के चल रहे किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

युवक के साथ 15 माह बाद मिली लापता बालिका

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। रिश्तेदार के यहां पंवासा थाना क्षेत्र के गलपुरा में रहने वाली नाबालिग 21 फरवरी 2025 को रात के समय लापता हो गई थी। परिवार के सभी जगह तलाश करने के बाद पुलिस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया था।

नाबालिग के पास मोबाइल नहीं था जिसके चलते उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। वहीं परिवार ने किसी युवक की जानकारी भी पुलिस को नहीं दी थी। जिसके चलते नाबालिग का पता नहीं चल पा रहा था। सालभर बीत जाने के बाद पंवासा थाना प्रभारी गमरसिंह मंडलोई ने पेंडिंग मामले का निराकरण करने के लिये एसआई नितेश मिठौरा, एएसआई संतोष राव आरक्षक पंकज पाटीदार और महिला आरक्षक निकिता पाटीदार की टीम गठित की। इस दौरान सामने आया कि नाबालिग राजगढ़ जिले की रहने वाली थी और 15 दिन पहले ही मां के साथ रिश्तेदार के यहां आई थी। पुलिस टीम द्वारा मुखबीर तंत्र को अलर्ट किया। तभी खबर मिली कि उक्त नाबालिग पचोर स्टेशन पर एक युवक के साथ दिखाई दी है।

टीम तत्काल पचोर स्टेशन पहुंची और आसपास के क्षेत्र में तलाश कर नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। उसके साथ सागर उर्फ रामसागर पिता बद्रीलाल केवट 23 साल निवासी गोपालपुर थाना सारंगपुर मिला।

दोनों को उज्जैन लाया गया। जहां सामने आया कि नाबालिग को युवक शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। युवक ने उसका शोषण भी किया है। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के साथ दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया। बुधवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। नाबालिग को परिजन अपने साथ ले गये है।

एसआई की सर्तकता से वापस सुरक्षित लौटी बालिका

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सूनासान रास्ता और रात केअंधेरे में तेजी से हाथ में बैग लेकर जाती बालिका को घर लौट रहे एसआई ने देखा तो बालिका को रोक लिया। बालिका घर छोड़कर भाग रही थी। एसआई ने अनहोनी होने से पहले उसे वापस सुरक्षित परिवार के सुपुर्द कर दिया। घट्टिया थाना एसआई अलकेश डांगे मंगलवार-बुधवार रात 1 बजे ड्युटी खत्म होने पर बाइक से घर लौट रहे थे। उसी दौरान थाना परिसर ग्राउंड की ओर से तहसील कार्यालय तरफ फोरलेन की ओर हाथ में बैग लेकर अकेली बालिका अंधेरे में सुनसान रास्ते पर दिखाई दी। एसआई ने बाइक घुमाई और बालिका के पास पहुंचकर उसे रोक लिया। पुलिस देख बालिका घबराने लगी, एसआई ने संवेदनशीलता दिखाते हुये परिवार के संबंध में जानकारी मांगी। बालिका ने बमुश्किल पिता का नम्बर दिया। जो थाना भवन के पीछे कालोनी के रहने वाले थे। एसआई ने पिता को कॉल किया और बालिका के बारे में पूछा। पिता ने घर में होने की बात कहीं, एसआई ने थाने बुलाया। बालिका को थाने लाया गया। माता-पिता के आने पर उन्होने बालिका को देखा तो हैरत में पड़ गये। बालिका से पूछताछ में सामने आया कि माता-पिता की डांट-फटकार से नाराज होकर बिना बताए घर से कहीं दूर जाने के लिये निकल गई थी। एसआई और पुलिस स्टॉफ ने बालिका के साथ परिजनों को समझाईश दी और बालिका को सुरक्षित घर भेज दिया। अगर बालिका और एसआई के आने-जाने में कुछ समय की देरी होती तो बालिका के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता था। बालिका 15 साल की होकर कक्षा 10 वीं की छात्रा थी।

सिंहस्थ कामों में सुस्ती, दो निर्माण एजेंसियों पर 1लाख 24 हजार की पेनल्टी

झालरिया मठ और भारत माता मंदिर-चौबीस खंभा मार्ग का काम धीमा मिला, अधिकारियों पर भी कार्रवाई

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ संबंधी निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। निरीक्षण के दौरान गुरुवार को काम की रफ्तार धीमी मिलने पर दो निर्माण एजेंसियों पर कुल 1 लाख 24 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण में स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा ने झालरिया मठ क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निर्माण एजेंसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं काम की निगरानी में लापरवाही सामने आने पर सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उपयंत्री के तीन दिन के वेतन कटौती के निर्देश दिए गए।

चौबीस खंभा मार्ग का काम भी धीमा मिला- इसके बाद भारत माता मंदिर से चौबीस खंभा मार्ग तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। 24 मीटर चौड़े और 360 मीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग का काम भी तय गति से नहीं चलता मिला। इस पर निर्माण एजेंसी पर 74 हजार रुपए की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए।

तो आगे भी होगी सख्त कार्रवाई- स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को संसाधन बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ से जुड़े सभी विकास कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। काम में देरी, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी मिलने पर जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उज्जैन को मिली 146 करोड़ से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी

नए पुल, सड़कें और मार्ग चौड़ीकरण को स्वीकृति- शिप्रा घाटों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ की तैयारियों को गति देते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में उज्जैन के लिए 146 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें नए पुल, सड़क निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिप्रा नदी के घाटों का निर्माण तय समय-सीमा में पूरा किया जाए तथा घाटों तक पहुंचने वाले मार्गों और पार्किंग की व्यवस्था भी साथ-साथ विकसित की जाए।

बैठक में मंजूर कार्यों में शनि मंदिर से प्रशांति धाम चौराहा मार्ग तक 30 करोड़ रुपए की लागत से पुल और एप्रोच रोड निर्माण, तपोभूमि-पिपलियाराघो पंचक्रोशी मार्ग पर कान्ह नदी पर 12 करोड़ रुपए का समानांतर पुल तथा तपोभूमि से गंगेड़ी होते हुए राघोपिपल्या तक 5.5 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क का निर्माण शामिल है। इस सड़क पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे।इसके अलावा देवास रोड से लालपुर होते हुए गरोठ मार्ग तक ढाई किलोमीटर लंबा फोरलेन पंचक्रोशी मार्ग 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। लेकोड़ा से टनकारिया रेलवे स्टेशन रोड तक 13.28 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी मंजूरी मिली है।

शहर के भीतर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए महाकाल थाना से चौबीस खंबा मार्ग तक 180 मीटर लंबी नई सड़क 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग से छोटी रपट तक सड़क चौड़ीकरण पर 36.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देवास रोड स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह और सर्किट हाउस के विस्तार एवं नवीनीकरण को भी स्वीकृति दी गई है।

घाटों के साथ विकसित होंगे पहुंच मार्ग और पार्किंग- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में शिप्रा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे घाटों की विशेष समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि घाटों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से तेजी से पूरा किया जाए। घाटों तक आने-जाने वाले मार्ग, पार्किंग स्थल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास भी समानांतर रूप से किया जाए ताकि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घाटों के पास स्थित आश्रमों और गुरुकुलों को घाट प्रबंधन से जोड़ा जाए। इससे सिंहस्थ के बाद भी घाटों का बेहतर रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और दीर्घकालिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में यह भी बताया गया कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही पंचक्रोशी मार्ग और शहर क्षेत्र में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाकर 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कोर्ट नजीर के मकान का बदमाशों ने तोड़ा ताला

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कोर्ट नजीर के मकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है। बदमाशों को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लग पाया सिर्फ नगदी चुरा कर ले गए हैं।

खाचरोद थाना पुलिस ने बताया कि ऑफीसर कॉलोनी में रहने वाले जलील पिता करीम खान कोर्ट में नजीर हैं। बुधवार को वह कोर्ट गए हुए थे उनके घर पर ताला लगा हुआ था परिवार के सदस्य भी बाहर गए हुए हैं। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके मकान का ताला तोड़कर पूरे घर की तलाशी ली कुछ हाथ नहीं लग पाया तो अलमारी में रखें 5 हजार रुपए नगद लेकर भाग निकले। शाम को मकान का ताला टूटा होने पर और घर में चोरी का पता चलने के बाद कोर्ट नजीर द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है।

इधर चलते ट्रक से चिया बीज चोरी- खाचरोद थाना क्षेत्र के ही ग्राम बेड़ावन्या में बदमाशों ने ट्रक कटिंग की वारदात को अंजाम दिया और तिरपाल काटकर उसमें रखी चिया बीज की 12 बोरी चोरी कर ली। चालक को घटना का पता चला तो उसने खाचरोद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार चालक आकाश पिता दादा राव महाराष्ट्र का रहने वाला है और महाराष्ट्र से ही बीज भर नीमच जा रहा था।

फर्जी मालिक बनकर महिला ने बेची 11 बीघा जमीन

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। फर्जी तरीके से जमीन का मालिक बनकर महिला ने 11 बीघा का सौदा कर दिया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री भी कर दी मामला उजागर होने पर पुलिस के पास पहुंचा महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है।

उन्हेल थाना पुलिस ने बताया कि ग्राम नवादा में मानी बाई पति शैतानमाल नाम की महिला का कुछ माह पूर्व निधन हो गया था। जिसके नाम पर 11 बीघा से अधिक जमीन थी। मानीबाई के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार दूर रहते है। ग्राम में उनकी जमीन ऐसे ही पड़ी थी जिसका फायदा उज्जैन की बड़ी मायापुरी में रहने वाली 60 वर्षीय महिला ने उठाया और खुद को जमीन का असली मालिक बातकर मानीबाई बनकर जमीन का सौदा ग्राम मकडावन में रहने वाली कविता दंडिग से कर दिया। फर्जी दस्तावेजों से कविता को रजिस्ट्री भी कर दी गई और लाखों रुपए ले लिया गए। कुछ दिन बाद कविता को अपने साथ धोखाधड़ी होने और जमीन दूसरी महिला के नाम पर होने का पता चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। जांच के बाद पुलिस ने मामले में तथाकथित मानीबाई के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। थाना प्रभारी संतोष चौहान के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दस्तावेजों को देखा जा रहा है। तथाकथित महिला की गिरफ्तारी के लिए टीम उज्जैन भेजी जा सकती है। विदित हो कि कुछ दिन पहले ही माधवनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिलीप सिंह बनकर ग्राम रलायता में जमीन का सौदा 1.39 करोड रुपए में कर दिया था और बदले में 36 लाख रुपए भी ले लिए थे। ग्राम मानपुर के ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तथा कथित दिलीप सिंह और सौदा करने वाले दलाल मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था जिसके विवेचना जारी है वहीं गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। माधव नगर थाना पुलिस के अनुसार हिरासत में आए दोनों आरोपी जिले में फर्जी जमीन मालिक बनकर धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं उनका पूरा गिरोह इसमें शामिल है। उन्हेल में दर्ज मामले के बाद पुलिस द्वारा कड़ियां जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है।